सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 130, नई दिल्ली । रविवार, 21 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा ।

03 बांसुरी स्वराज की सांसदी पर सवाल ! दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सोमनाथ

06 विकास के बजाय आरक्षण पर गिद्ध दृष्टि

08 आधुनिकीकरण की कमी के लिए पुस्तकालयों में कम उपस्थिति भी जिम्मेदार है

बारापुल्ला फेज-3 कॉरिडोर के पूरा होने की बढ़ी उम्मीद, नांगली राजपुर गांव में जमीन के 2 टुकड़ों के लिए मुआवजे का हुआ ऐलान

3.5 किलोमीटर लंबा बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर, जो सराय काले खां को मयूर विहार से जोड़ता है और इससे नोएडा, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर रहेगी। यमुना नदी के ऊपर एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए 274 पेड़ों को हटाने की अनुमति लंबित है।

नई दिल्ली: दिल्ली के बारापुला फेज-3 कॉरिडोर के पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने बरापुल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर के पूर्वी दिल्ली खंड के निर्माण के लिए नंगली राजापुर गांव में 1,169 वर्ग मीटर जमीन के अधिग्रहण के लिए मुआवजे की राशि की घोषणा भी की है। इसके साथ ही एक और बाधा दूर हो गई है। दक्षिण-पूर्व दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, भूमि मालिकों को मुआवजे के रूप में 11.18 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।

लोगों के लिए इसे खोलने में 6 महीने का समय लगेगा

अधिकारियों ने कहा कि तीसरे चरण में, 709.9 और 459.2 वर्ग मीटर के दो छोटे भूखंड ही ऐसे थे जिनका अधिग्रहण अभी तक नहीं किया गया था, जिससे यमुना के ऊपर 690 मीटर की कड़ी को पूर्व में मयूर विहार और पश्चिम में सराय काले खां से जोड़ा जा सके। ऐसा करने के साथ, अधिकारियों ने कहा कि उन्हें निर्माण पूरा करने के लिए केवल 274 पेड़ों को काटने और प्रत्यारोपित करने की अनुमति लेने की आवश्यकता है। एक अधिकारी ने कहा कि पेड़ काटने की अनुमति मिलने के दिन से हमें पुल का निर्माण पूरा करने और यात्रियों के लिए खोलने में छह महीने का समय लगेगा। मानसून के कारण सड़क का निर्माण अस्थायी रूप से रोक दिया गया है क्योंकि यमुना का जल स्तर बढ़ने की उम्मीद है और हरियाणा से और बाद में वजीराबाद बैराज से अधिक पानी छोड़े जाने से बाढ़ का मैदान भी जलमग्न हो सकता है।

कब शुरू हुआ था काम ?

3.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर काम 2015 में शुरू हुआ था, जिससे पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच यात्रा का समय सिर्फ 20 मिनट तक रहने का वादा किया गया था। हालांकि सड़क को खोलने की समय सीमा अक्टूबर है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसे बढ़ाना होगा। यह कॉरिडोर नोएडा, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के बीच यात्रा को तेज करेगा और हर दिन दो लाख से अधिक वाहनों के इस सड़क का उपयोग करने की उम्मीद है। इस सड़क से पूर्वी दिल्ली से एम्स पहुंचना आसान और जल्दी हो जाएगा। यह एनएच-24 पर यातायात को कम करेगा और पूर्वी दिल्ली और नोएडा से परिवहन केंद्र तक पहुंचना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, दो भूखंडों का अधिग्रहण करने की मंजूरी उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल नवंबर में दी थी. दिलचस्प बात यह है कि आठ साल पहले काम शुरू होने के बाद ही पीडब्ल्यूडी को पता चला कि उसके पास लगभग 8.5 एकड़ जमीन का स्वामित्व नहीं है, जो एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण थी। जहां एक तरफ पिछले कुछ सालों में 6 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, वहीं करीब 2.5 एकड़ के शेष हिस्से के बिना पीडब्ल्यूडी उन पर पांच पियर और लगभग 690 मीटर के स्पैन का निर्माण नहीं कर पाता।

इन्तहा हो गई इंतजार की... कब खुलेगा दिल्ली-सहारनपुर हाईवे? एक और डेडलाइन निकल गई

संजय बाटला

दिल्ली सहारनपुर हाईवे को खोलने की एक और तारीख बीत गई। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस हाईवे को खोलने को शुरू करने की तारीख दी गई हो। इससे पहले भी दो बार हाईवे को शुरू करने की डेडलाइन रखी गई थी लेकिन काम पूरा ही नहीं हुई था...

नई दिल्ली: दिल्ली-सहारनपुर हाईवे को शुरू करने की एक और डेडलाइन निकल गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी दो बार हाईवे शुरू करने की डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन हाईवे का काम पूरा न होने के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका। अब कयास लगाए जा रहे है कि हाईवे को अक्टूबर-नवंबर में शुरू किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसकी डेडलाइन बार-बार बढ़ाई जा रही है।

2019 में किया गया था शिलान्यास

दिल्ली-सहारनपुर हाईवे का शिलान्यास 2019 में किया गया था। साल 2022 में काम पूरा होना था, लेकिन कोरोना के कारण काम शुरू ही 2022 में हुआ। काम ने रफ्तार पकड़ी तो कहा गया कि मार्च 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन यह डेडलाइन भी निकल गई। इसके बाद जुलाई 2024 के रूप में नई डेडलाइन रखी गई, लेकिन इस बार भी ऐसा ही हुआ। प्रोजेक्ट से जुड़े एनएचएआई अधिकारियों का कहना है कि एलिवेटेड हिस्से में काफी हिस्से पर सड़क बनाने काम पूरा हो चुका है। स्ट्रीट लाइटें भी लग गई हैं। फिलहाल कई जगहों पर सर्विस रोड और सर्विस रोड के साथ गुजरने वाले नालों को बनाया जाना है। इसलिए अभी दिल्ली से सहारनपुर और देहरादून जाने का ख्वाब देखने वाले लोगों को कई महीने का इंतजार करना होगा।

गीता कॉलोनी श्मशान को किया जाएगा बंद

एनएचएआई ने गीता कॉलोनी श्मशान घाट के सामने बनी रेडलाइट को बंद कर दिया है। पुरानी दिल्ली और लक्ष्मी नगर की तरफ से आने वाले जिन लोगों को गीता कॉलोनी, राजगढ़ महिला कॉलोनी और गांधी नगर मार्केट की तरफ जाना है, उन्हें यहां से करीब 500 मीटर आगे से यू टर्न लेकर आना होगा। एनएचएआई का कहना है कि हाईवे शुरू होने के बाद जब ट्रैफिक तेजी से दौड़ेगा तो रेडलाइट ओपन होने के कारण यहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसलिए इस रेडलाइट को बंद करना जरूरी था। यहां बनी रेडलाइट को भी हटाया जाएगा। जहां रेडलाइट लगी हुई अभी वहां कुछ हिस्सा खुला हुआ है। उसे भी जल्द बंद कर दिया जाएगा।

संस्कारशाला : ध्यान का महत्व: नियमित ध्यान अभ्यास से धैर्य की कला सीखना

प्रियंका श्रीवास्तव

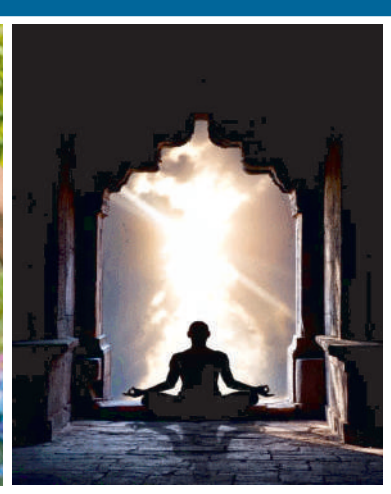

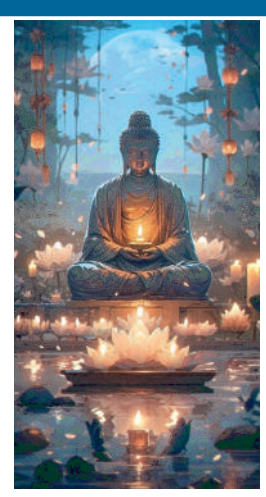

ध्यान, जिसे हम ध्यान या मेडिटेशन के नाम से जानते हैं, हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जब हम हर पल किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं, ध्यान हमें एक पल ठहरने और खुद के भीतर झांकने का अवसर प्रदान करता है।

ध्यान का मुख्य उद्देश्य है हमारे मन को शांति और स्पष्टता देना। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में, हम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं। नियमित ध्यान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यह हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करने, तनाव को कम करने, और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होता है।

धैर्य, जो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है, ध्यान के माध्यम से सहजता से सीखा जा सकता है। ध्यान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन के विचारों को नियंत्रित करें और धैर्यपूर्वक किसी भी परिस्थिति का सामना करें। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो हमारे मन में एक स्थिरता और संतुलन आता है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और शांति से कर पाते हैं।

ध्यान के नियमित अभ्यास से हम यह जान सकते हैं कि हमारे भीतर कितनी शक्ति और क्षमता है। यह हमें आत्म-नियंत्रण, आत्म-साक्षात्कार, और आत्म-विश्वास में वृद्धि करने में मदद करता है। जब हम अपने मन और आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तो हम जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं।

अतः, ध्यान का नियमित अभ्यास न केवल हमें मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, बल्कि यह हमें धैर्य और संतुलन की कला भी सिखाता है। यदि हम अपने जीवन में ध्यान को एक नियमित अभ्यास के रूप में अपनाते हैं, तो हम निश्चित रूप से एक सुखी, स्वस्थ, और संतुलित जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

हद ही हो गई ! दिल्ली मेट्रो में लोग अब फर्श पर लेटकर कर रहे सफर...

डीएमआरसी द्वारा मेट्रो में यह उद्घोषणा भी की जाती है कि मेट्रो के फर्श पर बैठकर कर सफर ना करें। मेट्रो के फर्श पर बैठकर सफर करना गैर कानूनी है। मेट्रो के फर्श पर बैठकर सफर करने पर जुर्माना हो सकता है। कई बार ऐसे यात्रियों का चालान भी किया जाता है। फिर भी कई बार यात्री मेट्रो के फर्श पर बैठकर सफर करने से बाज नहीं आते।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो का तरह-तरह के वीडियो, रील और फोटो वायरल होता रहता है। कभी कभी युवक युवतियों के डांस, कभी मारपीट तो कभी अश्लील हरकत का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है।

पुलिस की कार्रवाई और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की सख्ती के बावजूद ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। इसी क्रम में अब मेट्रो ट्रेन के फर्श पर लेट कर सफर करते एक यात्री का फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें यात्री मेट्रो के फर्श पर लेटा हुआ दिख रहा है।

यात्रियों को दूसरे कोच में जाने में हो रही थी दिक्कतें

किसी सह-यात्री ने उसकी फोटो लेकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया और डीएमआरसी से उसके खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत की। फोटो में वह यात्री मेट्रो ट्रेन के दो कोच के बीच वाली जगह के फर्श पर लेटा दिख रहा है। एक फोटो में वह मेट्रो ट्रेन के कोच पर एक तरफ सिर और दूसरी तरफ पैर रखकर लेटे दिख रहा है। इस वजह से यात्रियों एक कोच से दूसरे कोच में जाने में दिक्कत हो सकती है।

मेट्रो के फर्श पर बैठने पर है जुर्माने का प्रावधान

डीएमआरसी द्वारा मेट्रो में यह उद्घोषणा भी की जाती है कि मेट्रो के फर्श पर बैठकर कर सफर ना करें। मेट्रो के फर्श पर बैठकर सफर करना गैर कानूनी है। मेट्रो के फर्श पर बैठकर सफर करने पर जुर्माना हो सकता है। कई बार ऐसे यात्रियों का चालान भी किया जाता है। फिर भी कई बार यात्री मेट्रो के फर्श पर बैठकर सफर करने से बाज नहीं आते लेकिन इस मामले में तो यात्री ने हद ही कर दिया। वह मेट्रो के फर्श पर लेट गया।

वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

पर्यावरण पाठशाला: देशी वृक्षों का महत्व और जल संरक्षण में उनकी भूमिका : अंकुर शरण

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में देशभर में कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण पहल है 'पर्यावरण पाठशाला'। इस पहल का उद्देश्य लोगों को प्रकृति और वृक्षों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। खासतौर पर देशी वृक्षों की भूमिका और जल संरक्षण में उनके योगदान को समझाना है।

देशी वृक्षों का महत्व

देशी वृक्ष, जिनका हमारी भूमि, जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र से गहरा नाता है, हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये वृक्ष हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद करते हैं और विभिन्न प्रकार के जीव-जंतुओं को आवास प्रदान करते हैं। इसके साथ ही, देशी वृक्षों की जड़ें मिट्टी को मजबूती प्रदान करती हैं और जल संरक्षण में अहम भूमिका निभाती हैं।

वृक्षों की जड़ें और जल संरक्षण

वृक्षों की जड़ें प्रकृति का अद्भुत उपहार हैं। ये जड़ें पानी को धरती में गहराई तक पहुंचाने में मदद करती हैं, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है। वृक्षों की जड़ें पानी को सोखकर धरती के भीतर भेजती हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से वे जलस्रोतों को रिचार्ज करती हैं। इसके अलावा, वृक्षों की छाया से भूमि का तापमान कम होता है, जिससे वाष्पीकरण कम होता है और जल संरक्षण में मदद मिलती है।

वृक्ष: वर्षा के आकर्षण का साधन

वृक्षों की पत्तियाँ और छाल वाष्प को वातावरण में छोड़ती हैं, जो बादलों के निर्माण में सहायक होती हैं। यह वाष्पिकरण की प्रक्रिया वर्षा के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। वृक्ष, विशेष रूप से घने वन, वर्षा को आकर्षित करने में मदद करते हैं और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं।

महानगरों में जल संकट

आज के समय में महानगरों में भूजल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है। अंधाधुंध शहरीकरण, निर्माण कार्य और वृक्षों की कटाई से भूजल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। लोग सुंदरता और घरों में अधिक धूप के लिए वृक्षों की

कटाई कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण रूप से विकसित वृक्ष भी धीरे-धीरे मर रहे हैं।

वृक्षों का संरक्षण: एक सामूहिक जिम्मेदारी

वृक्षों की कटाई को रोकने और देशी वृक्षों के महत्व को समझने की आवश्यकता है। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वृक्षों का संरक्षण करना होगा।

पर्यावरण पाठशाला जैसे अभियान हमें यह समझने में मदद करते हैं कि वृक्ष केवल हमारे पर्यावरण को हरा-भरा ही नहीं रखते, बल्कि वे हमारे जल स्रोतों को भी समृद्ध करते हैं। आइए, हम सब मिलकर वृक्षारोपण करें और देशी वृक्षों का संरक्षण कर इस धरती को रहने योग्य बनाएँ।

पर्यावरण पाठशाला जैसे अभियान हमारी प्राकृतिक धरोहरों के महत्व को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देशी वृक्षों का संरक्षण केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य है। आइए, हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएँ और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए एक हरा-भरा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करें।

indiangreenbuddy@gmail.com

इनसाइड

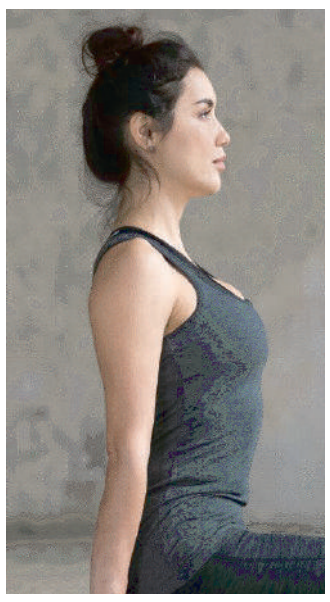

महिलाएं हर दिन करें ये 3 योगासन, बिना जिम के मिलेगा स्लिम-ट्रिम लुक

एक्सरसाइज या योग करना सेहत के लिए फायदेमंद है. नियमित योग और एक्सरसाइज करने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है. इससे कई बीमारियों से निजात भी मिलती है. बिजी रहने की वजह से या घर से बाहर न जाने की आदत के चलते कई बार महिलाओं के लिए जिम या योग केंद्र जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. कई बार महिलाएं चाहते हुए भी जिम नहीं जा पाती हैं और अपनी सेहत के साथ समझौता कर लेती हैं. हालांकि अगर आप चाहें तो घर में रहकर भी कुछ खास योगासन की मदद ले सकती हैं. जो आपको स्वस्थ रखने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं.

यूपी के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट की क्लीनिकल योग इंस्ट्रक्टर डॉ. वंदना अवस्थी से उन योगासनों के बारे में जानते हैं, जो आपको स्वस्थ रखने के साथ कई बीमारियों से राहत देने में मदद करेंगे. वैसे तो कोई भी आसन सुबह के समय करना बेहतर होता है लेकिन समय न मिलने पर जब भी करें तो खाना खाने के बाद कम से कम दो घंटे का गैप जरूर रखें. इतना ही नहीं इन योगासनों को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

चक्की चलनासन

इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट बिछाकर बैठ जायें. अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर मैक्सिमम गैप बनाएं. इस दौरान रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे. अब हाथों को जमीन पर एकदम सामने की ओर सीधा रखकर उंगलियों को आपस में फंसा लें. फिर अपने हाथों को क्लॉक वाइज यानी दायीं से बायीं तरह गोल-गोल उसी तरह से घुमायें जैसे चक्की चलाई जाती है. इसके बाद विपरीत दिशा में यही प्रक्रिया दोहराएं. इस योगासन को शुरू में एक-दो मिनट करें फिर धीरे-धीरे समय को बढ़ाएं. इस योगासन से पीसीओडी की दिक्कत में राहत मिलती है. जिससे अनियमित मासिक धर्म धीरे-धीरे नियमित होने लगता है साथ ही दर्द और ऐंठन से भी राहत मिलती है. इतना ही नहीं ये मेंटल स्ट्रेस को कम करने और मोटापे से निजात दिलाने में भी मदद करता है.

तितली आसन

तितली आसन करने के लिए योगा मैट पर सूर्य की ओर मुख कर के आराम की मुद्रा में बैठें. फिर अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर इस तरह से मोड़ें जिससे दोनों पैरों के तलवे आपस में मिल जायें. अब दोनों हाथों से पैर के तलवों को अच्छी तरह से पकड़ लें.अब तितली की तरह अपने पैरों को हिलाएं. इस आसन को भी शुरू में एक-दो मिनट करें फिर अपनी कैपिसिटी के अनुसार धीरे-धीरे इसका समय बढ़ाएं. तितली आसन करने से भी पीसीओडी की दिक्कत से राहत मिलती है. साथ ही पीठ का दर्द और मसल्स स्ट्रेस भी दूर होता है. इतना ही नहीं इस आसन को तीन महीने की गर्भावस्था के बाद भी किया जा सकता है. ये आसन डिलीवरी को आसान बनाने में भी मदद करता है. नियमित रूप से तितली आसन करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है.

दंडासन

दंडासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर बैठ जायें और पैरों को सामने की ओर फैला कर आपस में मिला लें. फिर दोनों हाथों को कंधों के बराबर अपनी जांघों के पास सीधा जमीन पर रखें.इस बीच रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें. अब दोनों पैरों के पंजो को अपनी ओर खींचें, कुछ सेकेंड रोक कर रखें फिर ढीला छोड़ दें. इस प्रक्रिया को दस से पंद्रह बार अपने सामर्थ्य के अनुसार दोहराएं. इस आसन को किसी भी आयु और अवस्था की महिलाएं आसानी से कर सकती हैं. दंडासन करने से कंधों में खिंचाव की दिक्कत कम होती है. रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत होती है, मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और पाचन शक्ति बढ़ती है।

महिला मित्रों की इन बातों से रहें आप भी सावधान !

बिना सोचे समझे हर सलाह को न करें स्वीकार

किसी के कहने पर दवाओं का सेवन करना हानिकारक हो सकता है. आजकल जिसे देखो वह दूसरों को बात-बात में सलाह देता रहता है. इनमें से कुछ एडवाइस काम की होती हैं और कुछ को ना मानना ही ठीक होता है. यदि आपकी भी सहेलियां, रिश्तेदार या फिर ऑफिस कलीग वजन घटाने, वर्कआउट करने, डाइटिंग करने या फिर मेकअप, पहनावे से लेकर रिलेशनशिप, करियर आदि पर सलाह देते हैं तो सुन जरूर लें, लेकिन फॉलो वही करें जो आपको अपने लिए सही और बेस्ट लगता हो. अक्सर दोस्त अपना समझकर नसीहत देते हैं, लेकिन उन्हें आंख मूंदकर मानने से बचना चाहिए. मित्रवत सलाह आमौतर पर लोग अपने अनुभवों और आपके प्रति चिंतित होकर देते हैं. ऐसे में जरूरी नहीं कि उन्हें जो चीज सूट करती हो, फायदेमंद साबित हुई हो, वह आपके लिए भी सही ही हो. खासकर, जब सलाह सेहत से संबंधित दी जा रही हो. न्यूवूमनइंडिया डॉट कॉममें छपी एक खबर के अनुसार, शारीरिक और साइकोलॉजिकल हेल्थ एडवाइस आप सिर्फ विशेषज्ञों या डॉक्टर की राय पर ही फॉलो करें. बेशक, आप अपनी दोस्त को अच्छी तरह से जानती-समझती हों, आप दोनों की दोस्ती कितनी भी अच्छी क्यों न हो, किसी विशेषज्ञ से सलाह लिए बिना किसी भी तरह की दोस्ताना सलाह लेने में नासमझी न करें. हम आपको यहां 4 फ्रेंडली एडवाइस के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें कभी भी आंख मूंदकर नहीं फॉलो करना चाहिए.

वर्कआउट

अक्सर जो लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं, वह सामने वाले को भी वही करने की सलाह देते हैं, जो वे खुद डेली रूटीन में करते हैं. यदि आपकी कोई दोस्त फिटनेस फ्रीक है और आपको वर्कआउट से संबंधित एडवाइस दे तो उसे सिर्फ जानकारी के तौर पर सुनें. आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, यह आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता. वर्कआउट करने से पहले आपको मेडिकल हिस्ट्री, परिवार में चली आ रही है बीमारियां, आपकी मेडिकल कंडीशन पर विचार करके ही वर्कआउट करने की योजना बनाएं. आप इसके लिए किसी फिटनेस एक्सपर्ट और ट्रेनर की सलाह जरूर ले लें.

खानपान की आदत

आपका जैसा खानपान होगा उसी अनुसार आपकी सेहत भी बनेगी. आप अपनी फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखकर ही अपना फूड इनटेक करें. आप दूसरों की सलाह पर अपनी डाइट तय ना करें. आपकी दोस्त कोई डाइट फॉलो कर रही है तो उसके कहने पर आप भी उन चीजों का सेवन ना करें. शरीर में विभिन्न हार्मोनल फंक्शन, पाचन एंजाइम्स के कार्यों, पोषक तत्वों की जरूरत और अधिकता के साथ-साथ आपके रक्त में कुछ घटकों के स्तर को समझने के बाद ही उचित डाइट किसी के लिए तय की जाती है. ऐसे में सिर्फ दोस्त के कहने पर कोई भी डाइट फॉलो करना सही नहीं है.

दवाओं का सेवन

फ्रेंड सर्किल में कोई ना कोई ऐसा होता है, जो हर कॉमन बीमारी के लिए दवा लेने की सलाह जरूर दे देगा. ये दवाएं निश्चित रूप से आपको आराम पहुंचा सकती हैं, लेकिन ये आपके शरीर के अनुकूल नहीं हुईं तो इनके कुछ साइड एफेक्ट्स भी हो सकते हैं. यह आपके महत्वपूर्ण अंगों को भी स्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए केवल उन्हीं दवाओं का सेवन करें, जो आपको डॉक्टर ने सलाह दी हो.

करियर और रिश्तों पर सलाह

जब आपके करियर और रिश्तों से जुड़े मुद्दों की बात आती है तो इसका फैसला आप खुद लें ना कि किसी के कहने पर आप अपने करियर और लाइफ पार्टनर का चुनाव करें. हर किसी की राय जानें, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ही उसका चुनाव करें. यदि आपकी दोस्त डॉक्टर बनना चाहती है तो आप भी वही करें, ये जरूरी नहीं है. सुनें सभी की, लेकिन करें अपने मन और इच्छानुसार. रिश्तों में भी वही बात शामिल है. यदि आपको कोई पसंद नहीं तो अपने दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर उससे किसी भी तरह के रिलेशन में ना बंधें.

कुछ सामान्य लक्षण जो 5 तरह के गाइनेकोलॉजिकल कैंसर में होते हैं कॉमन, आप भी दें ध्यान

कैंसर एक जानलेवा बीमारी है. यदि इसका समय रहते इलाज शुरू ना किया जाए तो कई गंभीर मामलों में व्यक्ति की जान चली जाती है. बॉडी में ट्यूमर सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ सिर्फ एक बॉडी पार्ट के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर के लिए खतरे की घंटी बन सकती है. कैंसर के कुछ ऐसे प्रकार हैं, जो सिर्फ महिलाओं को इनफेक्ट कर सकते हैं. ऐसे में महिलाओं में कैंसर की समस्या ज्यादा खतरनाक हो सकती है. ओवरीज, कोख या वेजाइना जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर असर करने वाले ये गाइनेकोलॉजिकल कैंसर ढेरों बड़ी परेशानियों का कारण बन सकते हैं. सही समाधान के लिए सही समय पर बीमारी की पहचान कर, सही इलाज कराना जरूरी है. दवाइयों के साथ सही ट्रीटमेंट की मदद से इन परेशानियों से निजात पाई जा सकती है. आइए जानते हैं 5 तरह के गाइनेकोलॉजिकल कैंसर में कौन से आम लक्षण देखे जाते हैं:

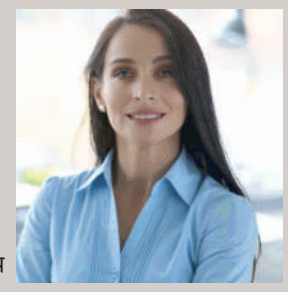

एमडैंडरसन डॉट ओआरजी के अनुसार, वुलवर कैंसर के अलावा सभी गाइनेकोलॉजिकल कैंसर में ब्लीडिंग की समस्या देखने को मिलती है. वेजाइना से किसी भी तरह के डिस्चार्ज या ब्लीडिंग को नजरंदाज करना घातक साबित हो सकता है. पेट दर्द के साथ ही कमर दर्द भी किसी बड़े खतरे की दस्तक हो सकती है. ऐसे में सही समय डॉक्टर से परामर्श अवश्य ले लें.

-बार-बार पेशाब आना किसी गंभीर स्थिति की ओर इशारा हो सकता है. लगातार टॉयलेट जाने की शिकायत कैंसर के साथ ही अन्य परेशानियों का भी लक्षण हो सकती है. ऐसे में जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह करा लें.

-वेजाइना या दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में खुजली, जलन और ज्यादा सेंसटिविटी कैंसर का लक्षण हो सकती है. इन्फेक्शन में भी ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं, ऐसे में इन्हें इग्नोर करने का रिस्क लेने से बचें.

-सेक्स के दौरान या बाद में ज्यादा असामान्य दर्द महसूस होने पर जरूरी टेस्ट अवश्य करा लें. ये दर्द गाइनेकोलॉजिकल कैंसर के शुरुवाती लक्षणों में शुमार है.

-पेडू या पेल्विक एरिया में दर्द होना कैंसर की ओर संकेत करता है. बार-बार इस तरह का दर्द होने पर डॉक्टर को अवश्य दिखा लें नहीं तो समस्या के गंभीर होने की संभावना बढ़ जाती है.

-खाना खाने में असहजता, पेट जल्दी भर जाना, भूख कम लगना या सूजन भी गाइनेकोलॉजिकल कैंसर का संकेत हो सकता है. ऐसे में घबराने की जगह सही उपचार का ख्याल करें.

स्ट्रॉन्ग वूमेन की 6 पहचान, जो उन्हें बनाती है सबसे अलग, आप खुद को कितना नंबर देंगी?

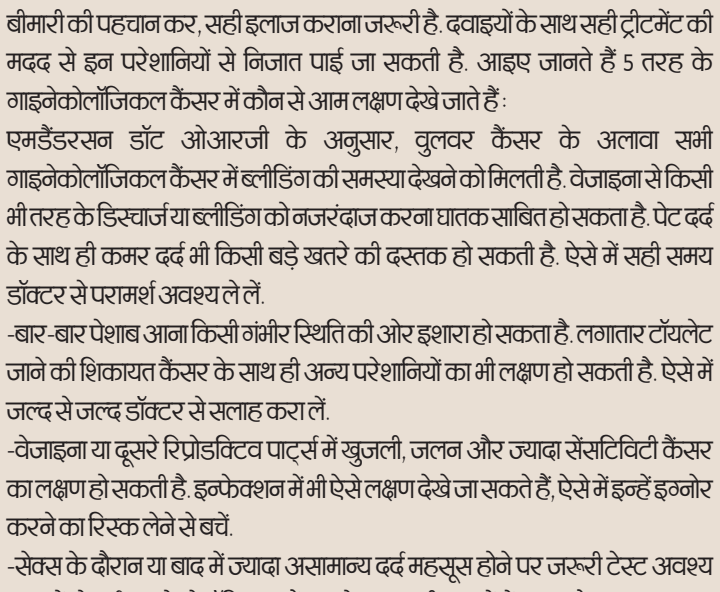

आमतौर पर हमारे देश में महिलाओं को काफी नाजुक और इमोशनली कमजोर माना जाता रहा है. लेकिन कई महिलाओं ने युवा लड़कियों के लिए उदाहरण पेश किया कि महिलाएं हर तरह से मजबूत हो सकती है और हर तरह की परिस्थितियों को बेहतर तरीके से डील कर सकती हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग वूमेन की क्या पहचान है और आप खुद को इस कैटेगरी में शामिल करती हैं या नहीं.

आप मानसिक रूप से कितनी मजबूत हैं, यह आपका 'आत्मविश्वास' बहुत अच्छी तरह से बताता है. जब आपके अंदर आत्मविश्वास होता है तो आप खुद का खास ख्याल रखती हैं और कभी भी खुद की तुलना दूसरों से नहीं करतीं. जिस वजह से ऐसी महिलाएं हमेशा खुश रहती हैं, इसलिए आत्मविश्वास किसी भी स्ट्रॉन्ग महिला की पहली पहचान मानी जाती है.

मजबूत सोच वाली महिलाएं अपने लाइफ को हमेशा प्रोडक्टिव बनाए रखती हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ बेहतर करने के प्रयास में रहती हैं. इस तरह वे जमाने के साथ अपडेट रहती हैं और उन्हें नए माहौल में एडजस्ट होने में मुश्किल नहीं आती.

मेंटली स्ट्रॉन्ग महिलाएं निराशावादी नहीं होतीं. उनके देखने का नजरिया काफी पॉजिटिव होता है और वे हर तरह से अपने आसपास गुड वाइब्स को क्रिएट करती रहती हैं. हां यह हो सकता है कि हर समय आशावाद और सकारात्मकता सोच संभव न हो, लेकिन जितनी बार वे विकास की मानसिकता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं, जिसकी वजह से उनका और उनके आसपास रहने वालों का मूड हमेशा बेहतर बना रहता है.

मानसिक रूप से मजबूत महिलाएं खुद का ख्याल रखने के साथ-साथ दूसरों का भी ख्याल रखती हैं, जिस वजह से उनका लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशन बना रहता है. दरअसल, जब आप लोगों की खुशी का परवाह करते हैं तो यह आपको भी खुशी देता है. यही सोच स्ट्रॉन्ग महिलाओं में भी होती है.

मानसिक रूप से मजबूत महिलाओं को लोगों की टिप्पणियों को नज़रअंदाज़ करने आता है और वे ₹नफरत करने वालों₹ पर आसानी से काबू पा सकती हैं. यही नहीं, उन्हें खुद पर विश्वास होता है और वे उन महिलाओं की मदद में भी आगे आती हैं जिनको मदद की जरूरत होती है. मानसिक रूप से मजबूत महिलाएं अपने डर, समस्याओं और मुद्दों का सामना करने में विश्वास रखती हैं और उन्हें उनसे सीधे निपटने में दिक्कत नहीं आती. कुछ गलत होने का डर या नकारात्मक रिजल्ड ना हो, यह सोचकर वे हालात से भागती नहीं और जब तक डर पर काबू ना पा लें, वे हालात को सीधा देखना पसंद करती हैं.

नशे की हालत में भी महिलाएं सनकी, लंपट पुरुषों की कर सकती हैं पहचान : रिसर्च

शराब पीना न सिर्फ सेहत के लिए हानिकारक होता है बल्कि ये हमारी मानसिक स्थिति को भी सीधे तौर पर प्रभावित करता है. शराब पीने के बाद व्यक्ति सही और गलत का निर्णय लेने तक में सक्षम नहीं रहता है, ऐसी सूरत में फिर चाहे पुरुष हो या महिला उसका आसानी से फायदा उठाया सकता है. नशे की हालत में सही व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता भी प्रभावित होती है. वैसे तो ये बात ठीक ही है लेकिन नशा की हुई महिलाओं के मामले में ये बात पूरी तरह से खरी उतरती नज़र नहीं आती है. हाल ही में एक रिसर्च में सामने आया है कि नशे की हालत में होने के बावजूद भी महिलाएं सनकी (Psychopaths) और धूर्त एवं दुष्ट प्रवत्ति (Narcissists) के लोगों की पहचान कर सकती हैं.

यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की डॉ. गेल ब्रेवर (Dr. Gayle Brewer) और उनकी टीम ने ये रिसर्च की है. Vice की खबर के अनुसार रिसर्च में ये पता लगाने की कोशिश की गई कि शराब पीने के बाद महिलाएं पुरुषों के व्यक्तित्व को कितना पहचान पाती हैं.

फोटो के जरिए कराई पर्सनैलिटी की पहचान

शराब के नशे में होने के बावजूद महिलाओं ने सनकी, धूर्त और लंपट पुरुषों की पहचान की. इस दौरान रिसर्च टीम ने महिलाओं को वोदका और लेमोनेट पिलाया. बता दें कि ये रिसर्च 96 महिलाओं पर की गई थी, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 26 साल के बीच थी. रिसर्च के दौरान नशा की हुई महिलाओं को कुछ पुरुषों के फोटोग्राफ दिखाए गए जिनके चेहरों से छेड़छाड़ की गई थी जिससे वे सनकी और धूर्त नज़र आएं. डॉ. ब्रेवर ने बताया कि 'हमने रिसर्च के दौरान क्लिनिकली डाइग्नोज किए गए किसी पुरुष का उपयोग नहीं किया, इसके बजाय उन फोटोज़ का उपयोग किया जिसमें पुरुष ज्यादा लंपट, सनकी या धूर्त नजर आए.' रिसर्च के दौरान पाया गया कि जिन पुरुषों के चेहरे ज्यादा सनकी या धूर्त नजर आए महिलाओं ने उन्हें नापसंद किया और उनके बारे में नकारात्मक राय दी.

डॉ. ब्रेवर ये भी कयास लगाती हैं कि महिलाओं में दुष्ट प्रवत्ति के पुरुषों को पहचानने की एक इनबिल्ट, अनकांशियस क्षमता एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज है. वे ये भी कहती हैं कि आप अल्कोहल को अपने निर्णय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं.

शराब के नशे में होने के बावजूद महिलाओं ने सनकी, धूर्त और लंपट पुरुषों की पहचान की. इस दौरान रिसर्च टीम ने महिलाओं को वोदका और लेमोनेट पिलाया. बता दें कि ये रिसर्च 96 महिलाओं पर की गई थी, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 26 साल के बीच थी. रिसर्च के दौरान नशा की हुई महिलाओं को कुछ पुरुषों के फोटोग्राफ दिखाए गए जिनके चेहरों से छेड़छाड़ की गई थी जिससे वे सनकी और धूर्त नज़र आएं.

बांसुरी स्वराज की सांसदी पर सवाल! दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सोमनाथ भारती, 22 जुलाई को होगी सुनवाई

सुषमा रानी

सोमनाथ भारती ने याचिका में आरोप लगाया कि आप के पूर्व मंत्री राज कुमार आनंद को वास्तव में याचिकाकर्ता के खिलाफ बांसुरी स्वराज की मदद करने के लिए खड़ा किया गया था। राज कुमार आनंद बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। वह नौ अप्रैल तक भारती के लिए प्रचार में सक्रिय थे और उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब वे भाजपा में शामिल हो गए।

नई दिल्ली। आप नेता सोमनाथ भारती ने कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा 22 जुलाई को चुनाव याचिका पर सुनवाई करने वाले हैं। याचिका में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार भारती को 3,74,815 वोट मिले, जबकि स्वराज को 4,53,185 वोट मिले। उन दोनों ने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और स्वराज को विजेता घोषित किया गया।

याचिका में कहा गया, ₹यह याचिका याचिकाकर्ता सोमनाथ भारती द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 और 81 के तहत नई दिल्ली से लोक सभा के सदस्य के रूप में बांसुरी स्वराज के चुनाव को चुनौती देते हुए दायर की जा रही है। 25 मई, 2024 को आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बांसुरी, उसके चुनाव एजेंट और प्रतिवादी की सहमति से अन्य व्यक्तियों द्वारा भ्रष्ट आचरण का प्रदर्शन किया गया।"

बांसुरी की मदद के लिए राजकुमार आनंद को खड़ा किया गया

याचिका में आरोप लगाया गया कि आप के पूर्व मंत्री राज कुमार आनंद को वास्तव में याचिकाकर्ता के खिलाफ बांसुरी स्वराज की मदद करने के लिए खड़ा किया गया था। हालांकि राज कुमार आनंद बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। इसमें कहा गया कि राज कुमार आनंद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और नौ अप्रैल तक भारती के लिए प्रचार में सक्रिय थे और अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

बूथ एजेंट बांसुरी को वोट करने के लिए कह रहे थे

याचिका में आरोप लगाया गया है कि वोट शेयर में कटौती करके स्वराज की मदद करने के लिए आनंद ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बाद में 10 जुलाई को वह भाजपा में शामिल हो गए। याचिका में दावा किया गया कि चुनाव के दिन याचिकाकर्ता नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के विभिन्न बूथों का दौरा किया। वह यह देखकर हैरान रह गए कि बूथ एजेंटों के पास बांसुरी स्वराज के मतपत्र संख्या प्रदर्शित करने वाले पर्चे थे।

एजेंट बांसुरी स्वराज की फोटो, चुनाव चिन्ह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो उन मतदाताओं को दिखा रहे थे, जो वोट देने के लिए बूथ पर पंक्ति में खड़े थे। वे उन्हें बांसुरी के लिए वोट करने के लिए कह रहे थे और ऐसा कृत्य निश्चित रूप से एक भ्रष्ट आचरण के योग्य है।

'हिंदुओं का सर्वनाश कर रही बीजेपी' : संजय सिंह

परिवहन विशेष न्यूज

आप सांसद संजय सिंह ने कहा- आपके पास इस बार एकतरफ बीजेपी के झूठ की गारंटी है तो दूसरी तरफ केजरीवाल जी की सब सच कर दिखाने की गारंटी है। आज हमने हरियाणा के लोगों को केजरीवाल जी की 5 गारंटी दी है। यह मोदी और सैनी के जुमले नहीं जो पूरे ना किए जाएं। यह केजरीवाल जी की गारंटी है जो वादे से ज्यादा काम करके दिखाते हैं।

नई दिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि BJP के सिर पर पिछले 10 वर्षों से सत्ता का नशा सवार है और इस नशे को आपको उतारना है। हरियाणा के गांव-गांव की सफाई के लिए झाड़ू चाहिए। इसके साथ ही BJP के सिर पर सवार सत्ता के नशे को भी इस बार आपको झाड़ू से ही उतारना है। BJP वालों ने आपको झूठ बोलकर आपको धोखा दिया है। इस बार आपको इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा- आपके पास इस बार एकतरफ बीजेपी के झूठ की गारंटी है तो दूसरी तरफ केजरीवाल जी की सब सच कर दिखाने की गारंटी है। आज हमने हरियाणा के लोगों को केजरीवाल जी की 5 गारंटी दी हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। यह कोई मोदी और सैनी के जुमले नहीं, जो पूरे ना किए जाएं। यह केजरीवाल जी की गारंटी है और केजरीवाल जी अपने वादे से ज्यादा काम करके दिखाते हैं। इसका उदाहरण दिल्ली है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में पूरी व्यवस्था बदल कर रख दी है। स्कूल और अस्पताल प्राइवेट से बेहतर हो गए हैं। आप सांसद ने कहा- BJP, हिंदुओं का सर्वनाश कर रही है। BJP को धर्म-जाति करने के अलावा कुछ नहीं आता है। इस देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। अगर अस्पताल बदहाल होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का होगा। अगर सरकारी स्कूल बदहाल है तो हिंदुओं के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। हिंदू ही सबसे ज्यादा किसान हैं अगर उन्हें MSP नहीं मिलेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का होगा।

दिल्ली में झुग्गियों को उजाड़ने से पहले सरकार उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें: देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि रेलवे लाईन के नजदीक बसी दया बस्ती व तुलसी नगर की झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस के बाद स्थानीय निवासियों में डर और चिंता बनी हुई थी। रेलवे द्वारा केन्द्र सरकार के इशारे पर उजाड़ी जाने वाली इन झुग्गियों के साथ ऐसा पहली बार नही हो रहा है इससे पहले भी रेलवे लाईन के नजदीक बसी झुग्गियों को उजाड़ने के बाद उन्हें बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी 2016-17 से लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी ने ही कोर्ट से स्टे लेकर इनको यहां से विस्थापित करने पर रोक लगाई थी।

उन्होंने ने दया बस्ती व तुलसी नगर झुग्गीवासियों से मुलाकात कर उनको आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कहा कि अगर कोई बुलडोजर झुग्गियों को तोड़ने आऐगा तो वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उपर से होकर झुग्गियों तक पहुँचेगा। यादव ने दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा यहां आने पर कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली में उजाड़ी जा रही झुग्गियों के लिए स्थाई रिहायश की व्यवस्था क्यों नही करती। गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की केजरीवाल सरकार की लम्बी परम्परा है।

उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के झुग्गियों को हटाना कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। क्योंकि इन झुग्गियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर कांग्रेस की याचिका पर आदेश आया था कि इन्हें वैकल्पिक स्थान दिए बिना उजाड़ा न जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों, झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोगों की सच्ची हितेषी है और दिल्ली में कहीं भी सरकार द्वारा गरीबों को उजाड़ा जाऐगा, हम उनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए मानवीय और कानूनी रुप से उनकी हर संभव मदद करेंगे।

फार्म हाउस मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए यूटीपेक से अप्रूव्ड डिजाइन के विपरित जाकर रिज के पेड़ काटे गए: सौरभ भारद्वाज

सुषमा रानी

नई दिल्ली, 20 जुलाई दिल्ली के रिज क्षेत्र में अवैध रूप से काटे गए 1100 पेड़ों के खिलाफ शनिवार को आम आदमी पार्टी ने ह्यूमन चेन बनाकर भाजपा और एलजी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी मुख्यालय पर एकत्र हुए ''आप'' कार्यकर्ता अपने हाथों में नारे लिखे पोस्टर-बैनर के साथ पेड़ का स्ट्रक्चर और आरी लिए थे। एलजी का मुखौटा पहने कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रतिकात्मक रूप से आरी से हरे पेड़ के स्ट्रक्चर को काटकर विरोध जताया। ''आप'' के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 03 फरवरी 2024 को मुख्य सचिव समेत अन्य वरिष्ठ अफसरों के साथ एलजी साहब रिज का दौरा करने गए थे और उसी दौरान 1100 पेड़ काटने के मौखिक आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार पूछा कि किसके आदेश पर इतने पेड़ काटे गए लेकिन अफसरों ने सच नहीं बताया। सड़क को चौड़ा करने के लिए फार्म हाउसों की जमीन ली जा सकती थी, लेकिन यहां फार्म हाउस मालिकों को फायदा पहुंचाना था। इसलिए रिज क्षेत्र के सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। इस दौरान विधायक राजेश गुप्ता, वरिष्ठ नेता रीना गुप्ता और आदिल समेत अन्य ''आप'' कार्यकर्ता मौजूद रहे।

विरोध प्रदर्शन के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार-बार डीडीए से सवाल पूछ रहा था कि उसने किसके आदेश पर गैरकानूनी तरीके से 1100 पेड़ काटे। लेकिन डीडीए के अफसर इसके पीछे की सच्चाई छिपाने में लगे हुए थे। 3 फरवरी को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, पीडब्ल्यूडी सचिव अनबरासू, पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह, डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी एलजी साहब के साथ रिज एरिया के दौरे पर गए थे। इसके बावजूद इनमें से किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात नहीं बताई कि एलजी साहब ने रिज एरिया का दौरा किया और पेड़ों को काटने के मौखिक निर्देश दिए।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात साफ हो गई है कि पेड़ों के काटने का आदेश एलजी वीके सक्सेना ने ही दिए थे। डीडीए के अधिकारियों की दो ईमेल से यह बात साफ पता चलती है। साथ ही, इस मामले में एक और बड़ा षड़यंत्र खुल कर आया है कि सड़क को चौड़ा करने के लिए जानबूझ कर रिज एरिया के पेड़ों को काटा गया, जबकि इसके लिए सड़क की दूसरी तरफ फार्म हाउस की जमीन भी ली जा सकती थीं। अगर वो हर फार्म हाउस से करीब 5 से 10 फीसद जमीन ले लेते, तो पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए सड़क चौड़ी की जा सकती थी। लेकिन ऐसा न कर फार्म हाउसों के मालिकों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से रिज के पेड़ों को काटा गया। अब ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई है। सड़क को चौड़ा करने का अप्रूव्ड डिजाइन आज भी यूटीपेक की वेबसाइट पर मौजूद है। इससे, साफ पता चलता है कि पेड़ों को काटने में भारी गड़बड़ी की गई है।

वहीं, दिल्ली के वजीरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता ने कहा कि पेड़ बेजुबान होते हैं। हालांकि उनमें जान होती है, वो सांस लेते हैं और सभी जीव-जंतुओं को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। एक पेड़ तीन पीढ़ियों को फल, ऑक्सीजन और छाया देता है। सब जानते हैं कि उत्तर भारत में प्रदूषण का बुरा हाल है। एक तरफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार पिछले 9 सालों से दिल्ली में करोड़ों पेड़ लगा रही है और अपने लक्ष्य से आगे चल रही है। देश के सभी महानगरों में दिल्ली की हरियाली सबसे ज्यादा है। हमने इसके लिए लगातार काम किया है। वहीं, दूसरी तरफ मोदी सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब ने दिल्ली के सेंसिटिव जोन से 1100 पेड़ कटवा दिए। यह एक प्रकार की जीव हत्या है। ये सोचने वाली बात है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं? चूंकि पेड़ बेजुबान हैं, वो खुद नहीं बोल सकते, इसलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक और पदाधिकारी पेड़ों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

केंद्र सरकार स्नातक मेडिकल/डेंटल प्रवेश परीक्षा नीट युजी के लिए महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है : विजय गर्ग

चूंकि सरकार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (एनईईटी-यूजी) को दोहरे आयोजकों के साथ दो स्तरीय परीक्षा प्रणाली में विभाजित करने पर विचार कर रही है। एक अन्य प्रमुख संशोधन की संभावना डिलीवरी के हाइब्रिड मोड में परिवर्तन है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, ऐसे कई विकल्प हैं जिन पर फिलहाल विचार किया जा रहा है, हालांकि नीट युजी 2024 के भाग्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, जो कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा देने की मांग भी शामिल है। कथित पेपर लीक के कारण 5 मई, 2024 को परीक्षा आयोजित की गई।

चर्चा के तहत कुछ बदलावों में एनईईटी-यूजी को दो-स्तरीय परीक्षा-प्रारंभिक और अंतिम में बदलना शामिल है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार, फाइनल के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीटों की संख्या से चार से पांच गुना होने की संभावना है, और पात्रता कटऑफ प्रारंभिक अंकों और कुल संख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी। सीटें. "इस बात पर भी विचार-विमर्श चल रहा है कि क्या प्रीलिम्स के लिए पेन-पेपर मोड को जारी रखते हुए फाइनल सीबीटी मोड पर दिया जा सकता है। एक अन्य पहलू पर गौर किया जा रहा है कि प्रीलिम्स और फाइनल के लिए अलग-अलग एजेंसियों को शामिल किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि प्रारंभिक परीक्षा होती है एनटीए द्वारा आयोजित, क्या फाइनल को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) / केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) / अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को सौंपा जा सकता है?" वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा।

सूत्र के मुताबिक, यह सुरक्षा की कई परतें पेश करने के लिए है। ₹अगर इसमें संदेह है कि कुछ उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में गलत तरीकों से प्रवेश करने में कामयाब रहे, क्योंकि हर साल संख्या बढ़ती जा रही है, तो फाइनल में जगह बनाना मुश्किल होगा।"

एनईईटी को पांच साल की कानूनी लड़ाई के बाद 2016 में पेश किया गया था जब 11 अप्रैल, 2016 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने अपने 2013 के फैसले को खारिज कर दिया, जिससे केंद्र की 21 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना को पुनर्जीवित किया गया, जिसमें एकल सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना शामिल थी। भारत में एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम। 1 मई, 2016 को सीबीएसई द्वारा आयोजित पहली एनईईटी के बाद से, जिसमें 6 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था, इस वर्ष 24 लाख से अधिक ने पंजीकरण कराया और 23 लाख से अधिक उपस्थित हुए, जिससे यह देश में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक बन गई, जिसमें लगभग 21 उम्मीदवारों का अनुपात था। प्रति सीट, और प्रति सरकारी सीट पर लगभग 42 उम्मीदवार।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब

सफदरजंग अस्पताल में मनाया गया बैंक ऑफ बड़ौदा का 117 वां स्थापना दिवस

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। सफदरजंग अस्पताल ने बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना दिवस मनाया। भारत के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में से एक सफदरजंग अस्पताल ने बैंक के 117वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) के योगदान के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। व्हीलचेयर, शिशु पुनर्जीवन मशीन, एयर गद्दे और फुट इंप्रेशन फोम सहित आवश्यक चिकित्सा उपकरणों से युक्त इस योगदान से अस्पताल के विभिन्न विभागों में रोगी देखभाल में उल्लेखनीय सुधार होगा।

सफदरजंग अस्पताल के अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पी.एस. भाटिया ने एक समारोह में नए उपकरणों का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया, जिसमें दोनों संस्थानों के प्रमुख लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जयंती मणि और डॉ. गौरव अरोड़ा, श्री सुधांशु एस. खमारी, उप महाप्रबंधक और श्री विशाल श्रीवास्तव एजीएम, मुख्य महाप्रबंधक श्री रोहित, बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रमुख और अस्पताल के विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। अपने संबोधन के दौरान, डॉ. भाटिया ने बैंक ऑफ बड़ौदा की पहल की सराहना करते हुए कहा, ₹बैंक ऑफ बड़ौदा का यह उदार योगदान निस्संदेह हमारे रोगियों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने की हमारी क्षमता को बढ़ाएगा। व्हीलचेयर जरूरतमंद लोगों के लिए गतिशीलता में सुधार करेगी, जबकि शिशु पुनर्जीवन मशीनें हमारी नवजात शिशु देखभाल इकाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। एयर गद्दे और फुट इंप्रेशन फोम उन रोगियों को बहुत लाभ पहुंचाएंगे जिन्हें दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता है और जिन्हें पैर से संबंधित समस्याएं हैं। ₹बैंक ऑफ बड़ौदा के डीजीएम श्री सुधांशु ने सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, ₹जैसा कि हम अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, हमें उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उनके मिशन में सफदरजंग अस्पताल के साथ साझेदारी करने का सम्मान है। यह योगदान समुदाय को वापस देने और जनता की सेवा करने वाले महत्वपूर्ण संस्थानों का समर्थन करने के लिए हमारे समर्पण को दर्शाता है। ₹ सफदरजंग अस्पताल और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच सहयोग एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे कॉर्पोरेट संस्थाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पहलों का प्रभावी ढंग से समर्थन कर सकती हैं। यह साझेदारी न केवल देखभाल के तत्काल प्राप्तकर्ताओं को लाभान्वित करती है बल्कि क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करती है।

डीडीए की जमीन पर बने श्मशान घाट पर चला बुलडोजर, विरोध में स्थानीय नागरिकों ने जमकर की नारेबाजी

परिवहन विशेष न्यूज

नरेला के स्वतंत्र नगर के पास बने श्मशानघाट पर डीडीए ने बुलडोजर चला दिया। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस कार्रवाई के विरोध में मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने डीडीए के खिलाफ नारेबाजी की और श्मशान घाट को दोबारा बनवाने का निर्णय लिया। निगम पार्षद दिनेश भारद्वाज ने सोमवार से धरना शुरू करने की घोषणा की।

दिल्ली। नरेला के बवाना रोड स्थित स्वतंत्र नगर के पास बने श्मशान घाट को डीडीए ने तोड़ दिया है। डीडीए का कहना है कि डीडीए की अधिग्रहित डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किया गया था, जिसे आज हटा दिया गया। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन डीडीए ने कार्रवाई नहीं रोकी। घंटेभर में डीडीए ने निर्माण ध्वस्त कर दिया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।

ग्रामीण रवीश भारद्वाज का कहना है कि आसपास कोई श्मशान भूमि नहीं होने के कारण ग्रामीणों व समाजसेवी संस्थाओं ने चंदा एकत्र कर 8-9 माह पहले श्मशान घाट का निर्माण किया था। रवीश ने बताया कि डीडीए ने निर्माण गिराने से पहले नोटिस दिया था। डीडीए द्वारा अधिग्रहित खाली जमीन पर हाल ही में श्मशान घाट बनाया गया था। इस जमीन को किसी को आवंटित नहीं किया गया था।

स्थानीय लोगों के लिए बांकानेर गांव में

ग्राम सभा की जमीन पर शमशान घाट पहले से ही मौजूद है। इसलिए, अतिक्रमण करने वालों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया और फिर क्षेत्र को साफ कर दिया गया। -प्रवक्ता, डीडीए

श्मशानघाट तोड़ने के विरोध में डीडीए के खिलाफ नारेबाजी

नरेला के स्वतंत्र नगर के पास बने श्मशानघाट पर बुलडोजर चलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस कार्रवाई के विरोध में जमा लोगों ने डीडीए के खिलाफ नारेबाजी की और श्मशान घाट को दोबारा बनवाने का निर्णय लिया। निगम पार्षद दिनेश भारद्वाज ने सोमवार से धरना शुरू करने की घोषणा की। लोगों के बीच पहुंचे स्थानीय विधायक शरद चौहान ने लोगों को भाजपा सांसद योगेंद्र चांदोलिया को साथ भी साथ लेकर श्मशान भूमि बचाने के लिए प्रयास करने की सलाह दी। डीडीए पहले ही कह चुका है कि उसकी अधिग्रहित जमीन पर श्मशानघाट बनाया गया था, जिसे ढहा दिया गया।

नोएडा में जीआईपी मॉल के सामने बनेगा श्रीनगर के लाल चौक जैसा घंटाघर, सेल्फी प्वाइंट के साथ होंगी ये सुविधाएं

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडावासियों के लिए खुशखबरी है। अब योगी आदित्यनाथ सरकार नोएडा के सेक्टर-38 ए स्थित जीआईपी मॉल के पास घंटाघर बनाएगी। जिसकी ऊचाई करीब 70 फीट होगी। अगर इसके डिजाइन की बात करें तो यह श्रीनगर के लाल चौक जैसा दिखेगा। इसको बनाने में लगभग 1.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका कलर लाल रंग का होगा। यहां पर सेल्फी प्वाइंट भी बनाया जाएगा।

नोएडा। सेक्टर-38 ए स्थित जीआईपी मॉल के सामने जल्द घंटाघर काम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए कार्य योजना को सैद्धांतिक मंजूरी प्राधिकरण सीईओ डॉ लोकेश एम ने दे दी है। जहां पर यह योजना धरातल पर उतारी जाएगी, उस जगह पर पुलिस चौकी को शिफ्ट किया जाएगा।

घंटाघर बनाने वाली कंपनी ही लगाएगी घड़ी

इसके लिए मार्किंग की जा रही है। बनाए जाने वाले घंटाघर की ऊंचाई करीब 70 फीट की होगी। इस घंटाघर में चारों ओर घड़ियां होंगी। यह घड़ी रोमन अंक में होंगी जो सोलर पैनल पर आधारित होंगी। घंटाघर बनाने वाली कंपनी ही घड़ी भी लगाएगी। इसका डिजाइन कुछ-कुछ श्रीनगर के लाल चौक से लिया गया है।

इसका कलर होगा लाल

हालांकि लाल चौक के घंटाघर (Lal Chowk Clock Tower) को फ्लोर में डिवाइड किया गया है। जबकि नोएडा में बनाया जा रहा घंटाघर में फ्लोर नहीं है। इसके निर्माण में करीब 1.40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कंपनी ने इसका डिजाइन भी प्राधिकरण को दिया है। इसका कलर लाल रंग का होगा।

साथ ही ऊपरी हिस्सा चोटी नुमा होगा। जिस पर तिरंगा फहराया जाएगा। घंटाघर के चारों ओर ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी, जिसमें बैठने के लिए बैंच होंगी। यहां सेल्फी प्वाइंट भी होगा। इस प्वाइंट को इस लिए चुना गया, क्योंकि यह रोड सीधे दिल्ली को जोड़ती है।

इसके एक तरफ माल और दूसरी तरफ नोएडा (Noida News) का वाणिज्यिक हब सेक्टर-18 है। ऐसे में यह घंटाघर नोएडा की सामरिक और आर्थिक दोनों ही उपलब्धियों का केंद्र भी होगा। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने बताया कि उद्यान विभाग की ग्लास हाउस, जापानी पगोडा, मंडपम वगैरह के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा।

इसके अलावा सोरखा में पुष्करिणी तालाब का निर्माण करीब 13 करोड़ में किया जाएगा। इस बजट पर सीईओ की मुहर लगना बाकी है। जल्द ही फाइल प्रस्तुत की जाएगी। नोएडा के उद्योग मार्ग को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके के लिए कंपनी का चयन होने जा रहा है।

गाजियाबाद बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम घोषित, दीपक शर्मा बने अध्यक्ष; सचिव पद प्रत्याशी धरने पर बैठे

गाजियाबाद। बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष दीपक शर्मा बन गए हैं शुक्रवार देर रात चली वोटो की गिनती में दीपक शर्मा विजयी घोषित किए गए। जबकि आज सुबह सचिव पद पर विजयी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई।

हरेंद्र गौतम को मिले 892 मत

चुनाव समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह यादव ने प्रत्याशियों को मिले मतों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सचिव पद प्रत्याशी हरेंद्र गौतम को 892 मत, अमित नेहरा को 891 मत, वरुण त्यागी को 754 वोट मिले जबकि 18 वोट अमान्य किए गए।

चुनाव समिति ने हरेंद्र को नहीं किया विजयी घोषित

चुनाव समिति के सदस्य ने हरेंद्र को सर्वाधिक मत प्राप्त प्रत्याशी बताया, लेकिन उनको विजय घोषित नहीं किया गया। इससे नाराज हरेंद्र गौतम अपने समर्थक अधिवक्ताओं के साथ बार सभागार के बाहर धरने पर बैठ गए हैं।

हरेंद्र गौतम का आरोप है कि उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई है। चुनाव में गड़बड़ी की गई है और छह बार काउंटिंग के बावजूद भी उनको सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर विजयी घोषित नहीं किया गया।

हरेंद्र गौतम का कहना है कि वह पुलिस को डीवीआर अपने कब्जे में लेने और मारपीट करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत देंगे। उनके एक साथी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सचिव पर पर कुल 2555 वोट की गिनती हुई जबकि वोट पड़े हैं 2553 ऐसे में वोटों का अंतर है। चुनाव समिति आज दिन में बैठक कर इसका समाधान निकलेगी।

29 जुलाई तक ED की कस्टडी में भेजे गए सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार, जांच एजेंसी ने देर रात की थी गिरफ्तारी

कांग्रेस के सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर अंबाला की कोर्ट में पेश किया जहां उन्हें 29 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े मामले में सुरेंद्र पंवार के साथ-साथ यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और करनाल में छापेमारी की गई थी।

सोनीपत। सोनीपत जिले से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पंवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को ईडी की टीम ने अंबाला की कोर्ट में पेश किया। अंबाला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने उन्हें 29 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद ईडी ने वापस उन्हें गुरुग्राम ऑफिस लेकर गए हैं। ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 9 दिनों की कस्टडी ही मंजूर की। सुरेंद्र पंवार की यह गिरफ्तारी देर रात हुई है। पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े मामले में सुरेंद्र पंवार, यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह (Dilbagh Singh) के यहां पर छापेमारी की गई थी।

ईडी पंवार के घर से ले गई थी कई दस्तावेज

इसके बाद ईडी पंवार के घर से कई दस्तावेज लेकर गई थी, इसी मामले में गिरफ्तारी बताई जा रही है। सेक्टर 15 स्थित विधायक की कोठी के सामने सन्नाटा पसरा है। रोजाना की तरह फरियादियों का जमावड़ा नहीं है।

अवैध खनन मामले में ईडी ने कसा शिकंजा

सीआईडी ने भी अधिकारियों को गिरफ्तारी की सूचना दी है। सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार के खिलाफ अवैध खनन मामले में ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है। जबकि कुछ समय पहले वह मामले की जांच करने आए थे।

सुरेंद्र पंवार विधानसभा की लेखा समिति के साथ 21 जून को अवैध खनन की जांच के लिए यमुनानगर खनन क्षेत्र का दौरा करने आए थे। उन्होंने अवैध खनन के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के साथ ही अधिकारियों की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा करते हुए काफी खिंचाई कर गए थे।

नोएडावासी खा रहे जहर! मैदा, सूजी, घी, पनीर और हल्दी के सैंपल हुए फेल; दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा के कई दुकानदारों के उत्पाद नकली पाए गए हैं। मैदा सूजी घी पनीर बेसन आरिगैनो कुट्टु आटा और हल्दी सहित 11 नमूने फेल साबित हुए हैं। इनमें नामी फूड चेन भी शामिल हैं। जिन दुकानदारों के सैंपल फेल हुए हैं उनके पास नमूनों की दोबारा जांच कराने का मौका है। वह केंद्र सरकार की लैब में जांच करा सकते हैं।

ग्रेटर नोएडा। मार्च से लेकर जून तक लिए गए खाद्य एवं पेय पदार्थों के नमूनों की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में मैदा, सूजी, घी, पनीर, बेसन, आरिगैनो, कुट्टु आटा और हल्दी सहित 11 नमूने फेल साबित हुए हैं। इनमें नामी फूड चेन भी शामिल हैं। खाने-पीने के सामान से खिलवाड़ करने वाले प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से समय-समय पर खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए लखनऊ लैब भेजा जाता है, जहां खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होती है।

दुकानदारों को नमूनों की दोबारा जांच कराने का मौका

सहायक आयुक्त खाद्य सर्वेश मिश्रा ने बताया कि नमूने की रिपोर्ट नकारात्मक आने के बाद प्रतिष्ठान संचालकों पर मुकदमा और जुर्माना लगाया जाता है। जिन दुकानदारों के सैंपल फेल हुए हैं, उनके पास नमूनों की दोबारा जांच कराने का मौका है। वह केंद्र सरकार की लैब में जांच करा सकते हैं। वहां नमूने फेल होने पर मुकदमा दर्ज होगा और जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

इन दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

दुकानदार नमूने

अन्नपूर्णा हॉस्टल, नॉलेज पार्क-तीन मैदा

जीएन हॉस्टल, नॉलेज पार्क-एक सूजी

मोर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेनो वेस्ट सूजी (मोर सेलेक्ट ब्रांड)

सुनील कुमार, बिसहाड़ा वेजिटेबल ग्रेवी

शाहरुख मलिक, गुरुद्वारा रोड घी

शाहनवाज, डाबरा गांव बेसन

जुबिलेंट फूड वर्क प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 37 नोएडा आरिगैनो

ब्लैक काफी कैफे, सेक्टर चार ग्रेटर नोएडा वेस्ट पनीर

आरएसके फूड स्पाइस प्राइवेट लिमिटेड, धूम मानिकपुर हल्दी

चौहान जनरल स्टोर, बरौला सेक्टर 49 कुट्टु आटा

डी वेल्व्स स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, नालेज पार्क-दो हल्दी

भारतीय परम्पराओं के अनुपालन से देश बढ़ रहा आगे

प्रह्लाद सबनानी

प्राचीन भारत में धार्मिक आयोजनों एवं धार्मिक पर्यटन का भारत के आर्थिक विकास पर पूर्ण प्रभाव रहा है। प्राचीन भारत में धार्मिक आयोजनों से अर्थव्यवस्था को बल मिलता रहा है इसलिए उस कालखंड में धार्मिक आयोजन निरंतर होते रहे हैं।

भारत जो किसी वक्त में सोने की चिड़िया रहा है जिसका किसी वक्त में वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उस भारत के गुलाम होने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था को मुगलों ने एवं अंग्रेजों ने तहस-नहस किया है। भारत का सनातन चिंतन जितना अधिक शक्तिशाली था गुलामी के उस दौर में उस पर किए गए आक्रमण उसे कमजोर बनाने में कामयाब रहे। परंतु, अब समय आ गया है कि भारत के प्राचीन आर्थिक चिंतन को गंभीरता के साथ देखते हुए वर्तमान आर्थिक विकास की दृष्टि को उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए तभी जाकर आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत के वैभवकाल को पुनः प्राप्त किया जा सकेगा।

भारत में प्राचीन ऋषियों और मनीषियों की परंपरा एक गृहस्थ परंपरा रही है और उस गृहस्थ परंपरा में आध्यात्म के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक चिंतन भी जुड़ा रहा है। अपने राज्य के ऋषियों के जीवन यापन की चिंता जहां राजा की प्राथमिकता में रहता था वहीं राजा को राज्य चलाने के लिए उचित मार्गदर्शन देने का सांस्कृतिक कार्य उन ऋषि-मुनियों द्वारा किया जाता था। इसलिए उन मनीषियों का चिंतन आर्थिक दिशा में भी सदैव बना रहता था। राजा अपने राज्य का विस्तार करने के साथ-साथ उसे आर्थिक रूप से और अधिक समृद्ध कैसे बनाएं इसके बारे में ऋषि-मुनियों के साथ बैठकर ही राज दरबार में चिंतन होता था और राज्य आर्थिक रूप से सशक्त बन जाते थे। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।

प्राचीन भारत में धार्मिक आयोजनों एवं धार्मिक पर्यटन का भारत के आर्थिक विकास पर पूर्ण प्रभाव रहा है। प्राचीन भारत में धार्मिक आयोजनों से अर्थव्यवस्था को बल मिलता रहा है इसलिए उस कालखंड में धार्मिक आयोजन निरंतर होते रहे हैं। भारत की ऋषि परंपरा ने जन सामान्य को उन सबके साथ जोड़ कर रखा था। त्यौहारों की निरंतरता और उन्हें मनाए जाने का उत्साह भारत की तत्कालीन अर्थव्यवस्था को गति देता रहा है। आज के वक्त में भी धार्मिक पर्यटन के चलते भारतीय पर्यटन उद्योग में रोजगार के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा भी पिछले 10 वर्षों में भारत में विभिन्न तीर्थस्थलों को विकसित किया जा रहा है। अभी तक जो तीर्थस्थल विकसित हो चुके हैं, वहां का पर्यटन एकदम से कई गुना बढ़ गया है। वहां की आर्थिक समृद्धि बढ़ गई है। वहां के लोगों का जीवन स्तर बढ़ गया है। वहां संपत्तियों के दाम बढ़ गए हैं। इसलिए इस दिशा में सरकार अब आगे और कार्य करने जा रही है तथा कई नवीन धार्मिक कारीडोर बनाने जा रही है, क्योंकि इससे रोजगार के लाखों नए अवसर उत्पन्न होंगे।

भारत की कुटुंब व्यवस्था अपने आप में एक अनूठी कुटुंब व्यवस्था है। भारत के संयुक्त परिवार विश्व के लिए आश्चर्य का विषय रहे हैं। इन दिनों संयुक्त परिवार विघटित अवश्य होते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके आपातकाल में एक दूसरे के लिए सबके एकत्र होने की जो जिजीविषा उन सबके भीतर है वह भारत में कुटुंब व्यवस्था का अनूठा स्वरूप है, तथा यह स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। एक परिवार में दो हाथ कमाने जाते हों और वहीं दस हाथ कमाने जाते हों, दोनों बातों का फर्क होता है। इसलिए कुटुंब व्यवस्था में एक दूसरे के लिए आपस में खड़े होने का जो व्यवहार होता है, वह व्यवहार आर्थिक चिंतन के साथ भी जुड़ कर परिवार को आगे बढ़ाने का काम करता है।

भारत में प्राचीन काल से पर्यावरण को पर्याप्त महत्व दिया जाता रहा है। देश में नदियां शुद्ध रहती थी वृक्ष घने जंगलों के रूप में रहते थे और पूरा पर्यावरण शुद्ध रहता था। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर नदियों को, वृक्षों को, धरती को पूजा जाता है। पूरे पर्यावरण से परिवार का जुड़ाव धार्मिक रूप से रहता है। बहुत सारे व्रत और त्यौहार पर्यावरण से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए सनातन काल से भारत में पर्यावरण की चिंता रही है। जैविक विविधता ने भी भारत के सनातन काल को समृद्ध किया। पर्यावरण संरक्षण को उस समय में नैतिक कर्तव्य माना गया है। बाद में जब मुगलों ने भारत में शासन किया और हिंदुओं का धर्मांतरण किया तो बहुत सारी परंपराएं भी खंडित होने लगी। सनातन काल में जिस गौ माता को पूजा जाता था मुस्लिम उस गौ माता को खाने लगे। मुस्लिम शासन काल भारत के पतन और विखंडन का समय था। उनके बाद जब इस देश में अंग्रेज आ गए तो उनकी निगाह में भारतीय अपरिपक्व और मूर्ख रहे इन दोनों के समय में, मुगलों ने और अंग्रेजों न भारत को दोनों हाथों से लूटकर खाली कर दिया। जो भारतीय अर्थव्यवस्था कभी विश्व की अर्थव्यवस्था का 33 प्रतिशत हिस्सा थी वह बहुत नीचे जा चुकी थी। पर्यावरण बिखरने लगा। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को नुकसान पहुंचाया गया। उसकी लाइब्रेरी को जला दिया गया। इस सब के पीछे भारत को ज्ञान के स्तर पर समाप्त करने की साजिश काम कर रही थी। मुस्लिम शासक हिंदुओं के धर्मांतरण पर, हिंदुओं को मारने पर और उनकी संपत्ति हड़पने पर काम कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ब्राह्मणों को मारकर रोज सवा मन जनेऊ जलाता था। मंदिरों को नष्ट कर उन पर मस्जिदें बना दी गई। दक्षिण ने अपने आपको इस मुस्लिम आक्रमण से बहुत बचाया और इसीलिए भारत के दक्षिण भाग में आज भी समृद्ध मंदिर हैं, जो उस कालखंड के गौरव की प्रस्तुति के रूप में हमारे सामने खड़े हुए हैं। इसी कालखंड में भारत का भक्ति काल जरूर समृद्ध हुआ और उसने भारत के निवासियों को मानसिक ताकत प्रदान की। तुलसीदास की भक्ति के सामने अकबर जैसा आदमी डर गया और झुक गया।

भारत की आजादी की लड़ाई तो सफलतापूर्वक लड़ी गई परंतु एक दुष्परिणाम भारत विभाजन के रूप में भी सामने आया, जिसमे लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ। आजादी के 70 वर्ष में भारत की वह आर्थिक उन्नति नहीं हो पाई जैसी कि अपेक्षा की गई थी। वर्ष 2014 में केंद्र में एक मजबूत सरकार ने शासन को संभाला। कठोर आर्थिक निर्णय लिए। जनता का भी उन्हें साथ मिला तथा लगभग 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई। वर्तमान सरकार के समक्ष बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और आज भारत, बहुत सी विदेशी ताकतों एवं उनके षड्यंत्रों के साथ जूझ रहा है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो संकल्प लेकर भारतीय परम्पराओं के अनुरूप सरकार काम कर रही है, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह इस अर्थव्यवस्था की ताकत है कि कोरोना खंडकाल में भारत ने अपने 80 करोड़ गरीब लोगों को निशुल्क अन्न उपलब्ध कराया तथा कोरोना की वैक्सीन भी समस्त नागरिकों को निशुल्क उपलब्ध कराई गई। भारत अब न सिर्फ सड़क निर्माण के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहा है, अपितु वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। साफ सफाई, गरीबों के लिए मकान, गरीबों के लिए शौचालय जैसे छोटे-छोटे विषय भी सरकार की प्राथमिकता में हैं। सरकार किसानों का ध्यान रख रही है, किसानों को समृद्ध बना रही है और उद्योगों को भी नई दिशा प्रदान कर रही है, नए संसाधन प्रदान कर रही है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत है कि जब विश्व के अन्य देशों में मंदी की स्थिति बन रही है और वहां की अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है तब भारत की अर्थव्यवस्था दिन-ब-दिन समृद्ध होती जा रही है।

देश में कुटीर एवं लघु उद्योग के गौरवशाली दिन वापिस लाने हेतु निरंतर कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन कर देश में सहकारिता आंदोलन को सफल होने का रास्ता खोला है। भारत के आर्थिक विकास में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थानों का भी बहुत बड़ा योगदान होने लगा है। बहुत सारे धार्मिक संस्थान बड़े-बड़े अस्पताल खोलकर सेवा का कार्य कर रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा इलाज की बहुत सारी सुविधाएं देश में कई अस्पतालों में मुफ्त में प्रदान की जा रही है। सरकार ने भी एम्स के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं सारे देश में उपलब्ध करवाने का काम किया है। विभिन्न सामाजिक संगठन भी अपना योगदान समाज की सेवा के साथ देश की अर्थव्यवस्था के विकास में प्रदान कर रहे हैं।

भारत का योग सारे विश्व के लिए मार्गदर्शक हो गया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के साथ अन्य राष्ट्र भी उन्नति करते जा रहे हैं। भारतीय नागरिक विदेशों में जाकर झंडे गाड़ रहे हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रवासी भारतीय कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारतीयों का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में प्रवासी भारतीय भी अपना योगदान कर रहे हैं। विश्व के कई देशों में भारतीय मूल के नागरिकों की बढ़ती संख्या एवं भारतीय सनातन दर्शन का प्रसार विदेशों में हो रहा है। भारत की तरह वहां पर भी मंदिरों का निर्माण हो रहा है। भारत की साधना पद्धति वहां स्वीकार की जाने लगी है।

-प्रहलाद सबनानी
सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक,

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

एमजी मोटर जल्द ही देश में 5 नई गाड़ियां करेगी लॉन्च

रिवहन विशेष न्यूज

एमजी मोटर भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने जा रही है। इसी क्रम में कंपनी 2025 तक देश में करीब 5 नई गाड़ियां लॉन्च करेगी। एमजी मोटर इन गाड़ियों को जेएसडब्लू ग्रुप के साथ साझेदारी में लॉन्च करेगी।

एमजी मोटर्स जल्द ही भारत में क्लाउड ईवी लॉन्च करने जा रही है। यह इलेक्ट्रिक कार एक बड़ी क्रॉसओवर होने वाली है। जानकारी के मुताबिक इस कार को अक्टूबर 2024 तक बाजार में उतारा जाएगा। इसके अलावा माना जा रहा है कि इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार की कीमत 10 से 20 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

एमजी की दूसरी इलेक्ट्रिक हैचबैक लॉन्च होने वाली है। इस कार का नाम बिंगो हो सकता है। हालांकि यह नाम बदल भी सकता है क्योंकि कंपनी ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। यह इलेक्ट्रिक कार मार्केट में टाटा टियागो ईवी को सीधी टक्कर दे सकेगी। इस कार में 31.9kWh का बैटरी पैक दिया जा सकता है। इस बैटरी की मदद से कार 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकेगी।

जानकारी के मुताबिक एमजी एक डी-सेगमेंट एसयूवी पर भी काम कर रही है। इस कार की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा हो सकती है। इस कार को इलेक्ट्रिक और PHEV इंजन के विकल्प के साथ बाजार में उतारा जा सकता है। यह कार एमजी वूलिंग कार पर आधारित हो सकती है।

इंदौर में रेवफिन का 'जागृति यात्रा अभियान' मध्य प्रदेश में ईवी क्रांति लाने और समाज में बदलाव लाने का वादा

परिवहन विशेष न्यूज

भारत की अग्रणी ईवी फाइनेंसिंग कंपनी रेवफिन ने मध्य प्रदेश में 'जागृति यात्रा अभियान' शुरू करके संधारणीय गतिशीलता में क्रांति लाने के अपने मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह पहल मध्य प्रदेश सरकार के इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के महत्वाकांक्षी एजेंडे के अनुरूप है, जैसा कि राज्य की व्यापक ईवी नीति में उल्लिखित है। नीति का लक्ष्य 2026 तक कुल वाहन पंजीकरण में ईवी की 25% हिस्सेदारी और 2028 तक राज्य के पांच प्रमुख शहरों में 100% इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन बसें हासिल करना है। यूपी में जागृति यात्रा के सफल लॉन्च के बाद, रेवफिन अब मध्य प्रदेश के बाजार को अपने अगले फोकस बाजार के रूप में देख रहा है, जहां अभियान को राज्य के पहले, मध्य और अंतिम मील वितरण प्रणालियों में वाणिज्यिक ईवी को अपनाने में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जागृति यात्रा अभियान के हिस्से के रूप में रेवफिन राज्य में अपना "ज़िम्मेदारी की सवारी" मार्केटिंग अभियान भी शुरू करेगा। यह अवधारणा ईवी को न केवल वाहन के रूप में प्रस्तुत करती है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन लाने और पर्यावरण की रक्षा करने के साधन के रूप में भी प्रस्तुत करती है। यह पहल मध्य प्रदेश में ईवी को अपनाने और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के व्यापक अभियान का समर्थन करती है, जिसमें 2027 तक 5,000 धीमी और तेज़ चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की राज्य की योजना भी शामिल है।

जागृति यात्रा के आयोजन में रेवफिन के संस्थापक और सीईओ समीर अग्रवाल ने शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के बढ़ते ईवी परिदृश्य और इस विकास को समर्थन देने के लिए रेवफिन की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर प्रकाश डाला। "इंदौर में ईवी की बढ़ती मांग और सतत गतिशीलता" पर एक ऊर्जावान रैपिड-फायर सत्र में उद्योग के नेताओं और ईवी डीलरों ने विकास के लिए सहयोगी रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए मजबूत भागीदारी की।

समीर अग्रवाल ने अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा, "मध्य प्रदेश एक इलेक्ट्रिक क्रांति के मुहाने पर खड़ा है और रेवफिन को इसका ध्वजवाहक होने पर गर्व है। पिछले छह महीनों में ही हमने लगभग 2,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्तपोषित करते हुए 30 करोड़ से अधिक के ऋण वितरित किए हैं। हमारे 'जागृति यात्रा अभियान' का लक्ष्य इस गति को बनाए रखना है, और हमारा लक्ष्य 2024 के अंत तक हमारे मासिक आवेदन दर में 30% की वृद्धि करना है। हम सिर्फ़ वाहनों को वित्तपोषित नहीं कर रहे हैं; हम राज्य में संधारणीय परिवहन की दिशा में एक आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं जो स्वच्छ हवा, आर्थिक सशक्तिकरण और सभी के लिए एक संधारणीय भविष्य का वादा करता है।"

रेवफ़िन ने मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, क्योंकि कंपनी ने पिछले छह महीनों में ही 30 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं। यह तेज़ वृद्धि राज्य में इलेक्ट्रिक परिवहन को अपनाने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने में रेवफ़िन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। कंपनी बजाज ऑटो, लेक्ट्रिक्स, बाउंस इनफिनिटी, काइनेटिक ग्रीन, उड़ान, टाटा मोटर्स, स्विच मोबिलिटी, यात्री, सिटी लाइफ़, मयूरी और ईवीज़ेड जैसे प्रमुख ओईएम के साथ अपनी साझेदारी का लाभ उठाकर अगले तीन वर्षों में 1000 करोड़ के ऋण वितरित करने की योजना बना रही है।

अपनी मुख्य पेशकशों के अलावा रेवफिन की नई पहल ₹रेवफिन मोबिलिटी₹ विशेष रूप से बेड़े के मालिकों को लक्षित कर रही है। यह पहल मध्य प्रदेश में मौजूद मध्यम दूरी और अंतिम मील वितरण में विशाल अवसर को समझती है, जिसकी शुरुआत इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और अन्य शहरों से होती है। प्रमुख साझेदारियों के माध्यम से, रेवफिन मोबिलिटी का लक्ष्य उस पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना है जो मूल्य श्रृंखला में वाणिज्यिक उपयोग के लिए ईवी को अपनाने में मदद करता है। अग्रवाल ने आगे कहा, ₹मध्य प्रदेश में हमारी सफलता राज्य के विकसित होते दृष्टिकोण और संधारणीय गतिशीलता की बढ़ती मांग का प्रमाण है। 'ज़िम्मेदारी की सवारी' के साथ, हम केवल ऋण नहीं दे रहे हैं; बल्कि, हम प्रत्येक नागरिक को एक स्वच्छ, अधिक पर्यावरण के अनुकूल और अधिक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने की ज़िम्मेदारी लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2026 तक कुल नए सार्वजनिक परिवहन में 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करके ईवी अपनाने में तेज़ी लाने के सरकार के एजेंडे का समर्थन करना है।" रेवफिन का अनूठा डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म और अभिनव अंडरराइटिंग दृष्टिकोण केवल 16 मिनट में ऋण स्वीकृत करने की अनुमति देता है, यहां तक कि बिना क्रेडिट इतिहास वाले आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए भी। यह तकनीक-संचालित मॉडल इसे तेजी से विस्तार करने और बाजार में गहरी पैठ हासिल करने की अनुमति देता है, जबकि पूरे राज्य में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाता है।

वर्तमान में मध्य प्रदेश के 54 शहरों में 100 डीलरों के साथ साझेदारी करते हुए, रेवफिन अगले साल तक और अधिक शहरों में विस्तार करके अपने नेटवर्क को दोगुना करने की योजना बना रहा है। कंपनी का लक्ष्य अगले 18 महीनों में अपने बाजार हिस्से को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 25% करना है।

इस 'जागृति यात्रा अभियान' का लक्ष्य केवल ईवी अपनाने के अभियान से कहीं अधिक है; यह शहरी विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है जो आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के साथ पर्यावरणीय चेतना को जोड़ता है। जबकि रेवफिन मध्य प्रदेश में विस्तार करना जारी रखता है, यह टिकाऊ गतिशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र विकास, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के अपने मूल सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है।

रामनगरी अयोध्या में अब महिलाएं चलायेंगी पिंक ई-रिक्शा

परिवहन विशेष न्यूज

रामनगरी अयोध्या में अब महिलाएं पिंक ई-रिक्शा चलाती नजर आएंगी। शहर में महिलाओं और लड़कियों के लिए अलग-अलग ई-रिक्शा चलाये जायेंगे। इनमें चालक भी महिलाएं ही होंगी। ये ई-रिक्शा पिंक रंग के होंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर निगम में ₹पिंक ई-रिक्शा परियोजना₹ पर काम शुरू कर दिया गया है।

परियोजना अधिकारी नगरीय विकास अभिकरण यामिनी रंजन ने बताया कि परियोजना के तहत शहर की महिलाओं को पिंक ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराये जायेंगे। ईटीओ मो. प्राइवेट लिमिटेड की मदद से इन महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा और प्रतिदिन 400 या 500 रुपये जमा करने होंगे। बाकी की कमाई उनकी आय होगी। साथ ही कंपनी पिंक ई-रिक्शा की पार्किंग, चार्जिंग, रखरखाव का काम करेगी।

उन्होंने कहा कि पिंक ई-रिक्शा से न केवल इन महिलाओं को आजीविका मिलेगी, बल्कि स्कूल-कॉलेज जाने वाली लड़कियों के अभिभावकों और प्रतिदिन शहर में आवागमन करने वाली महिलाओं की असुरक्षा की भावना भी दूर होगी। पीओ ने बताया कि पिंक ई-रिक्शा परियोजना के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से निशुल्क आवेदन लिए जा रहे हैं। जो महिलाएं समूह से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें भी डे एनयूएलएम योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा।

इन महिलाओं को ऑटो रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण भी निशुल्क दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। अब तक जिले में इस योजना का कुल लक्ष्य 50 महिलाओं का रखा गया है। जिसमें वर्तमान में 9 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। लक्ष्य के अनुरूप शेष महिलाओं के आवेदन और चयन की प्रक्रिया चल रही है। महिलाओं और लड़कियों के अधिक आने-जाने वाले मुख्य स्थानों, मुख्य बाजार, बस स्टैंड के पास, कॉलेज के पास ई-रिक्शा स्टैंड बनाए जाएंगे, ताकि इन ई-रिक्शा की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

दीपावली तक शुरू होंगे सभी एक्सप्रेसवे पर ईवी चार्जिंग स्टेशन

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तर प्रदेश के तीन बड़े एक्सप्रेसवे पर दीपावली तक ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हो जाएंगे। इन चार्जिंग स्टेशन के खुलने से दिल्ली से गाजीपुर, दिल्ली से चित्रकूट, लखनऊ-आगरा जैसे रूट पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से सफर तय कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण और इनकी देखरेख करने वाली संस्था यूपीडा ने इन आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू कर दिया है। अब आप अपनी ईवी को लेकर इन एक्सप्रेसवे पर टेंशनमुक्त यात्रा कर पाएंगे।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बना रही अडानी टोटल एनर्जी ई-मोबिलिटी लिमिटेड ने तीनों एक्सप्रेसवे पर काम शुरू कर दिया है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सितंबर तक आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ईवी चार्जिंग स्टेशन खुल जाएगा। इसके बाद अक्टूबर अंत तक पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग स्टेशन ऑपरेशनल हो जाएंगे। अधिकारी के मुताबिक एक एक्सप्रेसवे पर 8 चार्जिंग स्टेशन होंगे। जिसमें हर रूट पर 4-4 चार्जिंग स्टेशन होंगे। ये सभी चार्जिंग स्टेशन उन्हीं जगहों पर खुलेंगे जहां मौजूदा समय में पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन हैं।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ-साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भी दो चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज में भी बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। इसके लिए प्राधिकरण नगर निगम के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। जानकार मानते हैं कि एक्सप्रेसवे और हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन शुरू होने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में तेजी आएगी। मौजूदा समय में यूपी में करीब 8 हजार चार पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल और 1 लाख से अधिक दोपहिया ईवी गाड़ियां हैं।

एक्सप्रेसवे पर खुलने वाले चार्जिंग स्टेशन की दरें क्या होंगी? इस पर भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए हाल ही में यूपीडा के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी। इन व्यवस्थाओं के जरिए एक्सप्रेसवे के सफर को सुहाना बनाने की तैयारी है। लोगों को गाड़ी की चार्जिंग के लिए टेंशन नहीं होगी। ईवी से भी लोग अब लंबी यात्राएं कर पाएंगे।

ईवीएक्सपो 2024 का आयोजन 27 से 29 सितंबर के बीच तमिलनाडु के चेन्नई में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की अगुवाई में होगा

परिवहन विशेष न्यूज

ईवीएक्सपो जैसे एग्जीबीशन शो का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी यह हैं कि इस साल 2024 मे 27 से 29 सितंबर के बीच तमिलनाडु के चेन्नई में ईवीएक्सपो का आयोजन होने जा रहा हैं और मोबिलिटी सेक्टर की देश-विदेश की कंपनियां इनमें शिरकत करेंगी। साल 2015 से शुरू हुई यह एक्सपो दिन प्रतिदिन शानदार शुरुआत के साथ देश के हर कोने में आयोजित की जा रही हैं।

ईवीएक्सपो के आयोजक राजीव अरोड़ा ने अपने एक बयान में कहा कि ईवीएक्सपो में कमर्शियल और पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक वाहन कल-पुर्जे, टायर, बैटरी और ईवी से संबंधित उत्पाद और इलेक्ट्रिक वाहनों में लगे एकीकृत सॉफ्टवेयर शोकेस किए जाएंगे।

चेन्नई में ईवीएक्सपो आयोजन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की अगुवाई में होगा। इसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नॉलजी (ICAT), इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन (EVF), इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन (IFEVA) व इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (IFGE) की सक्रिय भागीदारी होगी।

बीआईटी सिंदरी में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों पर सात दिवसीय कार्यशाला की हुई शुरूआत

परिवहन विशेष न्यूज

बीआईटी सिंदरी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अपने प्लेटिनम जुबली समारोह के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके प्रमुख घटकों पर सात दिवसीय कार्यशाला शुक्रवार, 19 जुलाई को शुरू हुई। कार्यशाला के समन्वयक डॉ राहुल कुमार और डॉ मुरलीधर मनोहर ने इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी, प्रमुख घटकों, डिजाइन संबंधी विचारों और भविष्य की संभावनाओं में नवीनतम प्रगति का अवलोकन प्रस्तुत किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के एचओडी डॉ मोहम्मद अबुल कलाम ने इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित प्रमुख मुद्दों और अवसरों का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया।

कार्यशाला में उद्योग जगत की हस्तियों ने भाग लिया और अपने विचार रखे। इनमें अभिजीत कुलकर्णी, उत्पाद प्रबंधक डिजाइन टेक सिस्टम, अल्टेयर, क्षेत्रीय तकनीकी प्रबंधक संदीप यादव, संस्थापक सह सीईओ डेसिबल लैब्स सूरज, एसडीसीएफ डी इंजीनियर गौरव भट्ट, तकनीकी प्रबंधक संदीप रामगिरी, तकनीकी प्रबंधक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चंद्र कुमार, एम एप्लीकेशन इंजीनियर एचएफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एंजेल्स शायनी शामिल थे। यह कार्यशाला छात्रों, शोधकर्ताओं, संकाय सदस्यों और इलेक्ट्रिक वाहनों के उभरते क्षेत्र के पेशेवरों को भविष्य में चर्चा और सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।

बंगाल के बांकुरा में एक व्यक्ति ने बनाया 11 सीटों वाला ई-रिक्शा

परिवहन विशेष न्यूज

टोटो या इलेक्ट्रिक रिक्शा पश्चिम बंगाल में एक आम सार्वजनिक परिवहन है। हालांकि इसे पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, लेकिन इसमें बैठने की सीमाएँ हैं। एक पारंपरिक टोटो में केवल पाँच यात्री चालक सहित ही बैठ सकते हैं। साथ ही, सड़कों पर धक्कों के कारण होने वाले झटकों के कारण कई बार ई-रिक्शा की फिटिंग ढीली हो जाती है। लेकिन अब, बांकुरा के चंचल सिंह इन दोनों समस्याओं को हल करने के लिए एक बढ़िया उपाय लेकर आए हैं।

इससे पहले उन्होंने सिंह मोटर्स के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल जीप के अपने अभिनव निर्माण के लिए सुर्खियाँ बटोरी थीं। अब वे टोटो के लिए एक नया डिज़ाइन लेकर आए हैं। टोटो का यह नया मॉडल आसानी से एक फुटबॉल टीम को समायोजित कर सकता है। इसके एक साल तक इस्तेमाल करने के बाद भी इसमें कोई चरमराहट की आवाज़ या पुर्जे ढीले नहीं होंगे। उन्होंने 11 सीटों वाला मेगा ईवी टोटो डिज़ाइन किया है, जो बैटरी से चलेगा और इसे चलाने का खर्च भी बहुत कम होगा। उन्होंने इसे सिर्फ़ 1 लाख 20 हज़ार रुपये में बनाया है।

उन्होंने वाहन को स्टील से बनी बॉडी के साथ डिजाइन किया है और इसका सस्पेंशन सिस्टम आम इलेक्ट्रिक रिक्शा से काफी बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाला होगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। आम टोटो की बैटरी बिना बदले 2 से 2.5 साल तक चलती है। अगर कोई लिथियम बैटरी में अपग्रेड करता है, तो यह पांच साल तक चलेगी।

चचल सिंह का मानना है कि उनका 11 सीटर टोटो आपको काफी मुनाफा दिलाएगा। यह अनोखा टोटो बांकुड़ा की सड़कों पर दौड़ने लगा है। आप चाहें तो इसे अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं।

टोटो का अभिनव निर्माण दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा जिला किस तरह शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। यह चुनौतियों का डटकर सामना कर रहा है और उनसे निपटने के उपाय खोज रहा है। इससे पहले बांकुड़ा में सौर ऊर्जा से चलने वाला वाहन और अब ग्यारह सीटर ईवी टोटो का भी आविष्कार किया गया है।

विकास के बजाय आरक्षण पर गिद्ध दृष्टि

योगेंद्र योगी

सवाल यही है कि स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण देने की नेताओं जैसी कवायद यदि विदेशों में भी होने लगे तो लाखों की संख्या में रह रहे अप्रवासियों का क्या होगा। विदेशों में भी विपक्षी दल और आम लोग सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर अड़ जाएं तो स्थिति कितनी भयावह होगी'

देश में आरक्षण आंदोलनों से उपजी हिंसा और पड़ोसी देश बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर चल रही हिंसा और बवाल के बावजूद नेताओं का इस जहरीले दाव से वोट बैंक बनाए रखने का लालच खत्म नहीं हुआ है। बेशक इसके लिए देश की एकता-अखंडता से समझौता क्यों न करना पड़े। नेताओं को लगता है कि आरक्षण सबसे आसान रास्ता है वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। ऐसा इसलिए भी लगता है कि इससे आम लोगों को बरगलाया जा सकता है। उनका ध्यान देश के जरूरी बुनियादी मसलों से दिग्भ्रमित किया जा सकता है। बेशक आरक्षण की राजनीति से देश की एकता-अखंडता को कितना ही नुकसान क्यों न हो, पर नेता इस आग से खेलने से बाज नहीं आते हैं। देश की शीर्ष अदालत की निजी क्षेत्र में आरक्षण पर नजीर सामने होने के बावजूद नेताओं को वोट बैंक के लिए आसान रास्ता आरक्षण ही लगता है। इसके विपरीत रोजगार विकसित करने में सरकारों को पसीना आता है। इसके लिए पर्याप्त साधन-संसाधन चाहिए। भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की जरूरत है। यह सब करना नेताओं के बूते के बाहर है। सरकारी क्षेत्र में आरक्षण की संवैधानिक सीमा का नेता उल्लंघन नहीं कर सकते। हालांकि गाहे-बेगाहे यह प्रयास जारी रहता है। सरकारी स्तर पर आरक्षण नहीं मिलने पर नेताओं की गिद्ध दृष्टि खून-पसीने से तैयार हुए निजी क्षेत्र पर लगी हुई है। हालांकि नेता निजी क्षेत्र के जरिए ऐसा करके वोट बैंक बनाने के अपने नापाक मंसूबों में अभी तक विफल रहे हैं, किन्तु इसके प्रयासों में कोई कमी नहीं आई है।

नया मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने वोटों की नई पैंतरेबाजी के तहत निजी क्षेत्र में आरक्षण लाने का मंसूबा बना लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्राइवेट कंपनियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित कर दिया। इसका जब विरोध होना शुरू हुआ तो सरकार बैकफुट पर आ गई। इस फैसले को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह पहला मौका नहीं है जब देश के किसी राज्य ने बेरोजगारी की सच्चाई से मुंह मोड़ते हुए आरक्षण का सहारा लेने का प्रयास किया है। रोजगार विकसित करने के बजाय आरक्षण के ऐसे ही प्रयासों को लेकर कई दूसरे राज्यों को भी मुंह की खानी पड़ी है। सर्वाधिक आश्चर्य तो इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट निजी क्षेत्र में नौकरियों के आरक्षण के निर्णय को खारिज कर चुका है, उसके बावजूद नेताओं का लालच कम नहीं हो रहा। हरियाणा की भाजपा सरकार ने निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। इसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इससे कर्नाटक सरकार ने सबक नहीं सीखा कि यदि यह मुद्दा अदालत तक गया तो टिक नहीं पाएगा। इसी तरह वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने विधानसभा में निजी उद्योगों में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का बिल पास करा लिया था। बाद में यह मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा और उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह कानून असंवैधानिक हो सकता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2020 में निजी क्षेत्र में 80 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों को दिलाने की योजना पर तैयारी की गई थी। यह बदनियती भी सिरे नहीं चढ़ सकी। मध्य प्रदेश में तत्कालीन सीएम कमलनाथ ने निजी नौकरियों में 70 प्रतिशत सीटें स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए जाने के लिए कानून लाने की बात कही थी। बाद में जब बीजेपी की सरकार आई और शिवराज सिंह चौहान सीएम बने तो उन्होंने कहा, जो यहां का मूल निवासी है, वही शासकीय नौकरियों में आकर प्रदेश का भविष्य संवारे, यही मेरा सपना है।

हालांकि चौहान का यह सपना पूरा नहीं हो सका। कुछ ऐसा ही सस्ता राजनीतिक प्रयास तेलंगाना में केसी राव की सरकार के कार्यकाल के दौरान 2022 में भी किया गया। एक सरकारी सर्कुलर जारी करके निगम, संस्थाओं, बोर्ड और सोसाइटीज में 95 प्रतिशत छोटे-बड़े पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया गया था। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्राइवेट कंपनियों की 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय बेरोजगार युवकों को देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। यह प्रयास भी सफल नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल में जब पिछली बार टीएमसी की सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी कोशिश है कि राज्य सरकार की नौकरियों में स्थानीय लोगों को ही तरजीह मिले। उन्होंने कहा था कि बांग्लाभाषी लोगों को सरकारी नौकरियां मिलने से सरकार के कामों में आसानी होगी। हालांकि, निजी क्षेत्र के लिए इस तरह की कोई खास पहल सामने नहीं आई। यह प्रस्ताव बयानबाजी तक सीमित रहा। राज्यों की सरकारें वोट बैंक की खातिर आरक्षण की चाल चलती रही हैं। कुछ के दाव सफल भी रहे हैं। हालांकि मराठाभाषियों को आरक्षण दिए जाने का मुद्दा महाराष्ट्र में अभी तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। इसके बावजूद नेता भरसक प्रयास में जुटे हुए हैं। वोट बैंक के लिए आसान लगने वाला आरक्षण का रास्ता आग के दरिया से कम नहीं है। इसके बावजूद नेता आग से खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि मणिपुर का उदाहरण सामने है। मणिपुर पिछले एक वर्ष से अधिक समय से आरक्षण से लगी आग में अभी तक जल रहा है। मैतई समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हिंसा भड़की हुई है। इसी तरह जाटों और गूर्जरों के आंदोलन से उपजी हिंसा और अराजकता के निशान आज भी देश में बाकी हैं। लेकिन इससे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर हरियाणा में जमकर हिंसा, आगजनी व तोडफ़ोड़ हुई थी।

इस हिंसक आंदोलन में 30 लोगों की जान चली गई। गुजरात से पाटीदार आंदोलन में हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आईं। इलाके में कफ्र्यू लगाना पड़ गया था। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया था। आश्चर्य यह है कि नेताओं का ध्यान कभी भी रोजगार के स्थायी दीर्घकालिक समाधान की तरफ नहीं गया। इसके उदाहरण सामने हैं। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर स्थित एक होटल में एक निजी कंपनी में कुल 10 नौकरियों के लिए साक्षात्कार देने के लिए अंदर जाने के लिए भीड़ इतनी घनी थी कि उसने स्टील की रेलिंग को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह ढह गई और उसके साथ कई लोग नीचे गिर गए। इसी तरह मुंबई एयरपोर्ट पर लोडर के 600 पदों के लिए 25000 से ज्यादा आवेदक पहुंच गए थे। सवाल यही है कि स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण देने की नेताओं जैसी कवायद यदि विदेशों में भी होने लगे तो लाखों की संख्या में रह रहे अप्रवासियों का क्या होगा। भारत में नेताओं की तर्ज पर विदेशों में भी विपक्षी दल और आम लोग सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर अड़ जाएं तो कल्पना की जा सकती है कि स्थिति कितनी भयावह होगी। यदि ऐसे हालात बनते तब क्या विदेशों में जाकर भारत का हर क्षेत्र में परचम लहराया जा सकता था, जिस पर भारतीय गर्व से फूले नहीं समाते। नेताओं को चाहिए कि देश को बांटने के प्रयासों के बजाय समस्याओं के स्थायी समाधान पर ध्यान दें, अन्यथा उनके कुत्सित प्रयासों का संक्रामक यदि विदेशों तक फैल गया तो भारत की स्थिति बहुत भयावह होगी।

संपादक की कलम से

निशाने पर प्रधानमंत्री

संदर्भ मई, 2014 का है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में 10-12 दिन शेष थे। जाहिर है कि न तो जनादेश सार्वजनिक हुआ था और न ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। अलबत्ता मीडिया से संवाद और साक्षात्कार के दौरान उन्होंने यह जरूर कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी, तो 1993 के मुंबई सांप्रदायिक दंगों के आरोपियों को भारत लाएंगे। भाजपा के तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार मोदी ने अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहीम का भी जिक्र किया था कि उसे भी भारत लाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसे बयान सुनकर एक अन्य डॉन ने मीडिया के जरिए मोदी को मारने की धमकी दी थी। यह भी कहा था कि दाऊद को तब भारत ला पाएंगे, जब जिंदा बचेंगे। मीडिया के जिन चेहरों के जरिए वह धमकी दी गई थी, उन्होंने भारत सरकार में संबद्ध अधिकारियों को खुलासा कर दिया था। उसके बाद मोदी बीते 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और दाऊद को अभी तक भारत नहीं लाया जा सका है। हमारा विश्लेषण अंडरवल्र्ड डॉन को लेकर नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा हमारा चिंतित सरोकार है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा तो सार्वकालिक है, लेकिन अब यह अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर किए गए हमले के संदर्भ में ज्यादा प्रासंगिक है। उप्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा पर चिंता जताई है। उसके लिए मौजूदा नफरती राजनीति को ही बुनियादी कारण माना है कि प्रधानमंत्री लगातार निशाने पर रहते हैं। वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी की सलाह है कि प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर हिंसा, हत्या, मौत सरीखे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि ये किसी भी नागरिक को उकसा, भड़का सकते हैं। राजनीति में यह हिंसक प्रवृत्ति बीते एक दशक के दौरान ज्यादा बढ़ी है। सहिष्णुता और सद्भाव नगण्य-से होते जा रहे हैं। विपक्ष भाजपा-एनडीए की नीतियों का विरोध करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी को निजी तौर पर निशाना बना रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम चुनाव के दौरान जून में, वाराणसी में, प्रधानमंत्री के काफिले पर किसी ने चप्पल फेंकने का दुस्साहस किया। वह बम या ग्रेनेड भी हो सकता था। इस संदर्भ में राहुल गांधी की टिप्पणी थी कि अब लोग मोदी से डरते नहीं हैं। जब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए, तो उन्होंने अपने पहले भाषण में ही हिंसा और हत्या सरीखे शब्दों का कई बार इस्तेमाल किया। चप्पल फेंकना भी प्रधानमंत्री की चाक-चौबंद और अति प्रशिक्षित सुरक्षा-व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। पंजाब के फिरोजपुर इलाके में प्रधानमंत्री के काफिले को एक हाईवे पर अटक जाना पड़ा, तो उस स्थान पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जा सकता था! इन कथनों और घटनाओं के अलावा, पूर्वकेंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने बयान दिया था कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। मोदी की बोटी-बोटी करने का बयान देने वाला शख्स आज लोकसभा में कांग्रेस सांसद है। किसी ने यहां तक बयान दिया कि मोदी के सिर पर डंडे मारने चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसकी एक लंबी सूची है।

राजनीति में आजकल निजी प्रहार खूब किए जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी राजनेता की हैसियत से कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे थे, लेकिन उनके भाव मारने-काटने, हत्या कर देने या बेरोजगार युवा डंडे से पीटेंगे आदि नहीं थे। गौरतलब है कि मोदी देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। देश पहले भी दो प्रधानमंत्रियों की हत्या देख और झेल चुका है। दरअसल ये शब्द किसी को भी भड़का और उत्तेजित कर सकते हैं। उस मनोस्थिति में वह प्रधानमंत्री पर हमला कर सकता है। कई धमकीपूर्ण बयान किसान आंदोलन के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहे गए। कई राजनीतिक दल उन धमकीवालों के साथ खड़े रहे। 26 जनवरी, 2021 को तो दिल्ली में ऐसा उपद्रव मचाया गया, माना दिल्ली पर ही किसी बाहरी शक्ति ने आक्रमण किया हो! प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो चिंतित सरोकार है, लेकिन हमारी राजनीति की गरिमा, सभ्यता और शालीन व्यवहार भी दांव पर हैं कि हमारी राजनीति कितना नीचे तक गिर सकती है।

चर्चा

किसने रौंदे चाय के पौधे

तारीफ करनी होगी द्रंग, धोरण और घनेटा पंचायतों के लोगों की जो एक चाय के बागीचे को बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आश्चर्य यह कि एक बड़ा बागीचा बिका कैसे और चाय की पत्तियों को समाधि देकर एक धार्मिक स्थान इस जमीन की किस्म को कैसे बदल रहा है। चाय के बागीचों की खरीद-फरोख्त ने पहले भी कई काले अध्याय लिखे हैं और अब भी बेशर्मी के दाग चस्पां हैं। चाय के बागीचे इसलिए भी धरोहर हैं, क्योंकि इनके साथ सौ-सवा सौ साल का इतिहास व आर्थिकी चस्पां है। अगर हिमाचल के लैंड सीलिंग एक्ट के तहत बागीचों को छूट न मिली होती, तो चाय की सारी फिजा बर्बाद हो चुकी होती। हालांकि बागीचों की मूल भावना में पूरे चाय उद्योग के संरक्षण की ख्वाहिश थी, लेकिन छोटे-बड़े प्रभाव से ये बिकते रहे और आज स्थिति यह है कि पालमपुर जैसे शहर की इमारतों के नीचे चाय की पत्तियां रो रही हैं। बागीचों को उजाड़कर बस्तियां बनाने वाले कोई साधारण लोग नहीं, बल्कि राजनीतिक हस्तियों ने ऐसी बिकवालियों में खूब हाथ रंगे हैं। कहने को सरकारों ने बागीचों की बिक्री या बिक्री के लिए अनापत्ति देने पर रोक लगाई है, लेकिन परौर के समीप धार्मिक संस्थान की मिलकीयत में यह संदिग्ध सौदा हो जाता है। हैरानी यह कि लैंड सीलिंग जैसे एक्ट के बावजूद हिमाचल में नए लैंड लॉर्ड पैदा हो रहे हैं और इनमें भी कुछ धार्मिक संस्थाओं ने अपने आश्रमों के नीचे आकार में सबसे बड़े भूमि के सौदे किए हैं। इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में तीन-चार धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों का मूल्यांकन करें तो जंगलात महकमे के बाद उनकी भी एक जमीनी सत्ता है। इससे पहले भी कुछ चाय बागीचों की खरीद-फरोख्त में धांधली के आरोप लगे और कोर्ट कचहरी तक लोग गए, लेकिन चाय की मिलकीयत में वहां भी चाय ही पैदा हो रही है, जबकि परौर के समीप बागीचों से चाय की झाड़ियां हटा कर भूमि को समतल किया जा रहा है। पहले ही कांगड़ा चाय के बुरे दिनों पर मौसम व नीतियों की मार है, जबकि ऐसे मंसूबों से पूरी शिनाख्त ही खत्म हो जाएगी। कहां तो सरकार से यह गुजारिश है कि चाय की खेती को इसकी जड़ और इससे जुड़े श्रम तक को प्रोत्साहन मिले और कहां इसके अस्तित्व को रौंदा जा रहा है। द्रंग, धोरण और घनेटा की प्रबुद्ध जनता ने एक बड़े मसले, सामाजिक दायित्व, कानून की हद और भविष्य के प्रति परिवेश को जगाया है, तो सवाल इसकी जांच तक पहुंचते हैं। किस उद्देश्य से बागीचा बिका। किस शर्त और किस अनुमति से बिका। लैंड सीलिंग एक्ट के प्रश्रय में अब तक बचे चाय के बागीचे पर किसकी बुरी नजर लगी और ये कैसे धार्मिक संस्थान जो पैसे के दम पर जमीन पर कब्जा ही नहीं, बल्कि ऐसी खरीद से आर्थिकी की फसल उजाड़ रहे हैं।

हिमाचल में धार्मिक छत के नीचे फैलते भू-माफिया पर कड़ी निगाह ही नहीं, बल्कि इनके उद्देश्यों में पनपते साम्राज्यों की भी खबर लेनी होगी। हिमाचल में यूं तो जमीन खरीदने के जरूरतमंद हिमाचली भी आवासीय भूमि पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और इधर चाय के बागीचे को उजाड़कर धार्मिक साम्राज्य की हदें बढ़ाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार को मूल्यांकन करना चाहिए कि जिस जमीन को बचाने के लिए धारा 118 का मजबूत कवच बनाया गया है, उसके विपरीत धार्मिक प्रतिष्ठानों के कब्जे में आखिर बढ़ती सौदेबाजी के पीछे हैं कौन। यहां कांगड़ा के बागीचे की बिक्री से भी कहीं गंभीर प्रश्न चाय के पौधों को रौंद कर धार्मिक जलूस और जलसों का प्रबंध करना रहा है। इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से रोक ही नहीं, बल्कि पूरे सौदे का सत्य भी जनता के सामने लाना होगा।

डा. सुशील कुमार फुल्ल

क्या पेंशनरों की सिसकियां सुनेगी सरकार

पेंशनर्ज की सभा वेलफेयर सभा है और इसका प्रयत्न रहा है कि पेंशनर्ज की समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढा जाए। अति होने पर ही सभा हाईकोर्ट का द्वार खटखटाती है, परंतु सरकार की उदासीनता पेंशनरों को अखरती जरूर है'

पेंशनर्ज धरती के सबसे सुखी जीव होते हैं, परंतु तब तक जब तक उन्हें उनकी पेंशन नियमित रूप से मिलती रहती है। एक कहावत है कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाए तो पेंशन लग गई। इसका अभिप्रेत अर्थ यह भी है कि अब कोई चिंता की बात नहीं, काम करो या न करो। वैसे तो जीने का अधिकार सभी का है, परंतु क्या पेंशन का अधिकार सभी का नहीं होना चाहिए। एक देश एक शिक्षा नीति, वन रैंक वन पेंशन, एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे नारे प्रायः हवा में उछलते दिखाई देते हैं, परंतु क्या कभी सुना है कि देश में एक सी पेंशन हो। पेंशन की बात करना बर्र के छत्ते में हाथ डालना है, सो मैं अपनी बिरादरी की ही बात करूंगा, भले ही मेरे मन में यह विश्वास दृढ़ता से जमा हुआ है कि देश के सभी नागरिकों को जीवन निर्वाह योग्य पेंशन मिलनी ही चाहिए। सरकारी और सरकारी जैसी नौकरी की बातें जब कान में पडने लगती हैं, तो लगता है मानो किसी ने कानों में शीशा डाल दिया हो। कृषि महाविद्यालय, पालमपुर की स्थापना अगस्त, 1966 में हुई। कृषि विश्वविद्यालय बना प्रथम नवंबर सन-1978 को और सन-1970 से सन-78 तक महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का अंग रहा। तब पेंशन का प्रावधान नहीं था, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंड फंड का प्रावधान था। फिर धीरे धीरे लोगों का ध्यान पेंशन की ओर गया, क्योंकि सरकारी सेवा में तो शुरू से ही पेंशन थी। कृषि विश्वविद्यालय में पेंशन की अलख जगाने वाले अन्य लोगों के साथ साथ अधीक्षक सोम दत्त शर्मा का नाम प्रमुख रूप से कौंधता है। वह बड़ी बड़ी रिप्रेजेंटेशन बना कर राजनेताओं को देते रहे और यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी सरकार को भिजवाते रहे। उनके सर्विस काल में तो पेंशन संभव नहीं हो सकी, परंतु बीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में यह योजना साकार हो गई और यूनिवर्सिटी कर्मचारियों और अधिकारियों की बल्ले-बल्ले हो गई। पेंशन या सीपीएफ के लिए आप्शंज ली गईं। अधिकांश लोगों ने पेंशन के पक्ष में निर्णय लिया और लगभग अस्सी नब्बे लोगों ने सीपीएफ चुना क्योंकि उस समय की गणना के अनुसार सेवानिवृत्ति तक राशि निन्यानवे लाख तक बनती दिखाई देती थी, बाद में उनका क्या हुआ, प्रबुद्ध लोग जानते हैं। उन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। उल्लेखनीय है कि जब कृषि विश्वविद्यालय का गठन हुआ, उस समय के एक्ट तथा स्टैच्यूट्स में नियम 9 : 27 में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के समान होंगे अर्थात सेवा के नियमों, अधिनियमों में बराबरी का प्रावधान बना रहेगा। परंतु ज्यों-ज्यों आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं, सारी मार पेंशनरों पर पडने लगी है। अभी तक कुल 1734 पेंशनर्ज हैं, जिनमें से लगभग एक हजार पच्चास पंजीकृत सभा के सदस्य हैं। जो सेवारत कर्मचारी हैं, उनकी संख्या पेंशनर्ज से भी कम है। दस बारह वर्ष पहले किन्हीं कारणों से पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के पेंशनर्ज की पेंशन छह-सात महीने के लिए बंद हो गई थी। उस समय सभी ने उच्च न्यायालय तथा हिमाचल विधानसभा के माध्यम से मासिक पेंशन सुनिश्चित करवा ली थी, परंतु पेंशन के अतिरिक्त जो लाभ अर्थात नए वेतनमान के अनुसार संशोधित धन राशि, बकाया, कम्प्यूटेशन, लीव एन्कैशमेंट, मेडिकल बिलों का भुगतान, पेंशन भत्ते में उम्र 65, 70, 75 के अनुसार वृद्धि समय पर न मिलना पेंशनर्ज को परेशान करता है। सन-2022 से मेडिकल बिलों का रुका भुगतान रोगग्रस्त पेंशनर्ज को सिसकने के लिए विवश कर देता है। क्या कोई इन सिसकियों को सुनने का प्रयास भी करता है? पेंशनर्ज के पूरे भुगतान के लिए जितना धन चाहिए, उससे बीस-पच्चीस करोड़ प्रति वर्ष कम मिलता है।

एरियर लम्बित होते जाते हैं। वित्त नियंत्रक और कुलपति पालमपुर से शिमला की सडक़ें नापते रहते हैं। फिर पेंशनर्ज सभा बार-बार माननीय उच्च न्यायालय, शिमला में याचिकाएं डालती रहती है और उसे मेरिट के आधार पर राहत मिलती भी है। और यदि यूनिवर्सिटी नियमानुसार समय पर पेंशन और दूसरे लाभ देती रहे, तो सभा कोर्ट में क्यों जाए। दोनों तरफ का कोर्ट खर्चा और समय की बरबादी बच सकती है। अभी भी कई याचिकाएं हाईकोर्ट के विचाराधीन हैं। प्रायः सुनने में आता है कि विश्वविद्यालय को वार्षिक ग्रांट पूरी नहीं मिलती और कभी-कभी तो यह भी कहा जाता है कि 'जेनरेट यौर ओन फंड्ज', जैसे कोई उकताया हुआ बाप अपने बेटे से कहे- अपना कमाओ और खाओ। ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है। कृषि शिक्षा को समर्पित यह यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसमें विद्या प्रसार प्रमुख लक्ष्य है। प्रसार और अनुसंधान भी इसके लक्ष्यों में है, परंतु यह व्यापारिक स्थल नहीं है। फिर भी पेड सीट्स से कुछ धनार्जन होता है। कुछ विभागों में रिवाल्विंग फंड भी होता है, परंतु उससे इतना धनार्जन नहीं होता कि यूनिवर्सिटी का व्यय पूरा हो जाए। आश्चर्य होता है कि विश्वविद्यालय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए तो सेंटर से खूब धन आता है, परंतु ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत कम, सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और परिणामतः यूनिवर्सिटी को जब कुछ देना होता है या कोई बकाया देना होता है, तो प्रबंध बोर्ड में निर्णय ले लिया जाता है कि विद इमिडिएट इफेक्ट। जब पैसा होगा तो बकाया दे दिया जाएगा। न पैसा होगा, न बकाया दिया जाएगा, प्रायः यही स्थिति बनी रहती है और पेंशनर छटपटाते रहते हैं, सिसकियां भरते हैं और अस्पताल के लाखों के बिल उनका मुंह चिढ़ाते रहते हैं। कुछ समस्याएं इसलिए भी पैदा होती हैं कि वेतन आयोगों की सिफारिशें समय पर लागू नहीं की जातीं, परिणामस्वरूप एरियर का बकाया बढ़ता जाता है और पेंशन यूनिवर्सिटी के लिए टेंशन बन जाती है। पेंशनर्ज की सभा वेलफेयर सभा है और इसका प्रयत्न रहा है कि पेंशनर्ज की समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढा जाए। अति होने पर ही सभा हाईकोर्ट का द्वार खटखटाती है, परंतु सरकार की उदासीनता अखरती जरूर है। पेंशनर्ज की सिसकियों को सरकार को सुनना चाहिए, यह स्वस्थ और सदाशयपूर्ण पग होगा। यदि भविष्य में ऐसा नहीं होगा तो फिर बूढ़े सत्तर या अस्सी पार के पेंशनर एसडीएम पालमपुर से अनुमति लेकर चढियार रोड पर धरना देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। पेंशनरों की बात सुनी जाए।

अपने-अपने मंथन

चुनाव का मौसम निकल गया है। आजकल बरसात का मौसम भी चल रहा है और मंथन का मौसम भी चल रहा है। यानी दो मौसम एक साथ चल रहे हैं। बरसात का और बादलों का कोई भरोसा नहीं होता। कभी भी कहीं भी बरस सकते हैं। कहीं पर भी बाढ़ ला सकते हैं। कहीं पर बादल फट भी सकते हैं, क्योंकि बरसात में अक्सर ऐसा हो जाता है। इसी तरह मंथन का मौसम भी चल रहा है। मजे की बात यह है कि सत्ता पक्ष भी मंथन कर रहा है और विपक्ष भी मंथन कर रहा है। दोनों पक्षों के हाईकमान द्वारा भेजी गई नेताओं की टोलियां अपनी अपनी हार का मंथन कर रही हैं। एक टोली यह मंथन कर रही है कि लोकसभा चुनाव में हमारा सुपड़ा साफ कैसे हो गया? दूसरे दल की टोली इस मंथन में जुटी है कि उपचुनाव में जीत हमारे हाथ से क्यों फिसल गई? दोनों तरफ मंथन चल रहा है। दोनों तरफ भितरघात की शिकायत हो रही है। दोनों तरफ लावा उबल रहा है। ऊपर ऊपर से यह दिखाया जा रहा है कि मंथन बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ है। मंथन करने आए नेता अच्छे होटल में ठहराए गए हैं। उनके हर सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यानी पूरी खातिरदारी हो रही है। सेवा भाव में कोई कमी नहीं रखी जा रही। नेता लोग भी विस्तार से मंथन कर रहे हैं।

मंथन में मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि मीडिया के जाने से मंथन में खलल पड़ जाता है और और बीच की खबर बाहर आ जाती है। बीच की खबर चर्चा का विषय बन जाती है और मंथन की हवा निकल जाती है। इसलिए बंद कमरे में मंथन हो रहा है। जो चुनाव हार गए हैं, वे मोटी मोटी फाइलें अपने साथ लेकर आए हैं। इन फाइलों में भितरघातियों के नाम दर्ज हैं। यानी सबूत सामने रखे जा रहे हैं। मंथन करने वाले नेताओं की आंखें आश्चर्य से फटी जा रही हैं। ऐसा दोनों दलों के मंथन में हो रहा है। यह मंथन समंदर मंथन की तरह नहीं है जिसमें अमृत निकल रहा हो। इसमें विष निकल रहा है। एक दूसरे के प्रति विष उगला जा रहा है। यह सारा विष हाईकमानों के सामने रखा जाएगा। हाईकमान फिर मंथन करेगा। उसके बाद मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा कि बहुत शानदार मंथन हुआ। पार्टी की साख बढ़ी है। पब्लिक ने भरोसा कायम रखा है। अगले चुनाव की तैयारी में अभी से सभी को कमर कस लेने के लिए कहा गया है। 'अनुशासन सर्वोपरि है' की घुट्टी सभी कार्यकर्ताओं को पिला दी गई है। यह घुट्टी पीने के बाद कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। अब सिर्फ जोश में होश कायम रखना है।

पार्टी का अगला मंथन किसी अन्य पर्यटन स्थल पर होगा और अगले चुनाव के नतीजे आने के बाद होगा, यह भी मीडिया को ब्रीफ कर दिया गया है। यानी मंथन बैठक के बाद जो कुछ होना है, उसका खाका पहले से तैयार है। फिलहाल मंथन चल रहा है। अंदर मंथन हो रहा है और बाहर बारिश हो रही है। मंथन करने दिल्ली से आए नेताओं को गर्मी से राहत मिल रही है। इससे बढिया मंथन और क्या हो सकता है? यहां चिंता सिर्फ एक ही है कि कहीं बारिश मंथन के नतीजे पर पानी न फेर दे। एक और कमाल की बात देखिए। अलग-अलग जगह पर मंथन चल रहा है और अलग-अलग दलों के कार्यकर्ता बड़ी उत्सुकता से मंथन की आउटपुट का इंतजार कर रहे हैं। एक होटल के बाहर खड़ा एक दल का कार्यकर्ता दूसरे दल के कार्यकर्ता से पूछ रहा है। 'इस मंथन का क्या आउटपुट आएगा?' जवाब मिल रहा है- 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया।' फिर दोनों दलों के कार्यकर्ता ठहाके लगा रहे हैं।

गुरमीत बेदी

ईपीएफओ अधिकारियों ने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जताई चिंता, अपग्रेड और सुधार की जरूरत

परिवहन विशेष न्यूज

ईपीएफ अधिकारी संघ के अधिकारियों ने केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखा है। इसमें ईपीएफ आईटी सिस्टम – सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आईटी मैनपावर – को अपग्रेड करने के लिए तुरंत कदम उठाने की गुजारिश की गई है। स्थिति अब गंभीर हो गई है क्योंकि अधिकारी और कार्यालय रोजाना महत्वपूर्ण सिस्टम कमियों की रिपोर्ट कर रहे हैं। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) अधिकारी संघ ने सेवानिवृत्ति निधि निकाय के सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है।

इस सप्ताह की शुरुआत में मंत्री को लिखे पत्र में, ईपीएफ अधिकारी संघ (EPFOA) ने कहा कि वह ईपीएफ आईटी सिस्टम - सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आईटी मैनपावर - को अपग्रेड करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप के लिए नियमित रूप से अनुरोध प्रस्तुत कर रहा है, जिससे ईपीएफ मैनपावर पर भारी दबाव पड़ रहा है और EPFO सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

गंभीर हो गई है स्थिति

एसोसिएशन ने कहा कि स्थिति अब गंभीर हो गई है, क्योंकि अधिकारी और कार्यालय रोजाना महत्वपूर्ण सिस्टम कमियों की रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि EPFO आईटी सिस्टम की अपर्याप्तता और इसके परिणामस्वरूप सेवा संबंधी बाधाएं ईपीएफ सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं।

EPFO एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसकी सेवा वितरण बुनियादी ढांचे के आधारभूत घटक के रूप में कार्य करता है।संगठन ने कहा कि यह प्राथमिक मंच है जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्रीय कार्यालय सदस्य दावों की प्रक्रिया और निर्णय लेते हैं।

हाल के दिनों में, सॉफ्टवेयर ने महत्वपूर्ण अस्थिरता प्रदर्शित की है, जिसमें बार-बार व्यवधान आना शामिल है। पिछले कई हफ्तों में, एप्लीकेशन का प्रदर्शन खराब हो गया है, जो बार-बार सिस्टम धीमा होने, अनैच्छिक उपयोगकर्ता लॉगआउट और पूर्ण सिस्टम विफलताओं के रूप में प्रकट होता है। इससे पहले, EPFO प्रबंधन ने सॉफ्टवेयर प्रदर्शन समस्याओं को समवर्ती उपयोगकर्ता लॉगिन के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

हालांकि, इसने कहा कि स्थिति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है जहां भारी उपयोगकर्ता यातायात की अनुपस्थिति में भी सिस्टम क्रैश और धीमा हो जाता है। यह देखा गया है कि फील्ड ऑफिस ने ऑफ-पीक घंटों के दौरान भी सिस्टम विफलताओं की सूचना दी है।

EPFO एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सुधार की जरूरत

इसने कहा कि EPFO एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के व्यापक ओवरहाल की आवश्यकता पिछले कुछ समय से स्पष्ट है। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता के बावजूद, इस तरह के ओवरहाल के कार्यान्वयन को अस्पष्ट कारणों से बार-बार स्थगित कर दिया गया है।

EPFO एक वित्तीय रूप से मजबूत संगठन है, जो सरकारी प्रशासनिक निधि से स्वतंत्र है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2.0 संस्करण को लॉन्च करने में देरी आयकर विभाग जैसे अन्य विभागों द्वारा हासिल की गई तीव्र तकनीकी प्रगति के विपरीत है। EPFOA ने बताया कि यह विसंगति स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने में प्रणालीगत विफलता को दर्शाती है।

किसी भी तकनीकी चुनौती का जोरदार तरीके से खंडन किया गया है और कथित प्रगति पर जोर दिया गया है। यह अनुमान लगाना उचित है कि दावा निपटान प्रक्रिया पूरी तरह कार्यात्मक सॉफ्टवेयर प्रणाली के साथ तेजी से बढ़ेगी।

निराश है कर्मचारी और अधिकारी

EPFOA ने पत्र में कहा कि हम सम्मानपूर्वक आपसे तत्काल ध्यान देने का आग्रह करते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की लगातार कमियों और ऊपरी प्रबंधन की कथित गैर-जिम्मेदारी के कारण EPFO अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जा रही बढ़ती निराशा पर है।

इसने सुझाव दिया कि मुद्दों के मूल कारणों का निदान करने और दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठन के रूप में EPFO की स्थिति के अनुरूप एक समकालीन सॉफ्टवेयर समाधान विकसित करने के लिए अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों द्वारा सॉफ्टवेयर का व्यापक मूल्यांकन अनिवार्य है। संस्था ने कहा कि पिछले तीस महीनों में, हमने लगातार सीपीएफसी के ध्यान में EPFO के आईटी बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को लाया है।

सप्ताह भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों ने डाले 15,420 करोड़ रुपये

19 जुलाई तक एफपीआई घरेलू इक्विटी बाजारों में 30772 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष 2024 में शुद्ध एफपीआई निवेश 33973 करोड़ रुपये हो गया है। इससे पहले जून में भी एफपीआई ने 26565 करोड़ रुपये का निवेश किया था। पिछले सप्ताह एफपीआई ने इक्विटी बाजारों में 15420 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

नई दिल्ली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का जुलाई के दौरान भारतीय इक्विटी यानी शेयर बाजारों में निवेश जारी है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के डाटा के अनुसार, 19 जुलाई तक एफपीआई घरेलू इक्विटी बाजारों में 30,772 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष 2024 में शुद्ध एफपीआई निवेश 33,973 करोड़ रुपये हो गया है।

इससे पहले जून में भी एफपीआई ने 26,565 करोड़ रुपये का निवेश किया था। पिछले सप्ताह एफपीआई ने इक्विटी बाजारों में 15,420 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके साथ 2024 में एफपीआई का भारत में कुल निवेश 1,30,138 करोड़ रुपये हो गया है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी शोध प्रमुख श्रीकांत चौहान का कहना है कि बेहतर तिमाही नतीजों और बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी के चलते बीते सप्ताह बाजारों में मजबूत रही है। आने वाले सप्ताह में एफपीआई निवेश अस्थिर रह सकता है।

बीते सप्ताह भारत समेत ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया के बाजारों में एफपीआई ने निवेश किया। दूसरी ओर, ताइवान, थाइलैंड और वियतनाम के बाजारों से निकासी की गई। घरेलू बांड या डेट बाजारों की बात करें तो एफपीआई 19 जुलाई तक 13,573 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। इससे पहले जून में बॉन्ड बाजारों में 14,955 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था। 2024 में अब तक डेट बाजारों में एफपीआई का कुल निवेश 82,198 करोड़ रुपये हो गया है।

पहली छमाही में घरेलू कारोबारी भरोसा सूचकांक बढ़ा, 30 प्रतिशत कंपनियां नई नियुक्ति करने की

परिवहन विशेष न्यूज

50 प्रतिशत कंपनियां अगले छह महीनों में प्रबंधकीय और कुशल श्रमिकों के वेतन में भी बढ़ोतरी करने जा रही है। एनसीएईआर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले छह महीनों में कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होने की उम्मीद मौजूदा निवेश का माहौल और वर्तमान में उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता के अधिकतम उपयोग से कारोबारी भरोसा सूचकांक में बढ़ोतरी हो रही है।

नई दिल्ली। पिछले छह महीनों में कारोबारी माहौल के सूचकांक में मजबूती आई है और इसे देखते हुए अधिकतर कंपनियां अगले छह महीनों में कुशल व गैर कुशल सभी प्रकार के नए श्रमिकों की नियुक्ति करने की तैयारी करती दिख रही हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकोनामिक रिसर्च (एनसीएईआर) की तरफ से कारोबारी भरोसा सूचकांक पर जारी रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी-मार्च की तिमाही में कारोबारी भरोसा सूचकांक 138.2 था जो इस साल अप्रैल-जून में बढ़कर 149.8 हो गया। पिछले साल जनवरी-मार्च में यह सूचकांक 128 था। इस भरोसे को देखते हुए इस साल अप्रैल-जून तिमाही में 32.3 प्रतिशत कंपनियों ने बताया कि वे कुशल व अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की नई नियुक्ति करने जा रही है। इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में 30 प्रतिशत कंपनियां नई नियुक्ति करने की तैयारी कर रही थी।

अप्रैल-जून तिमाही में 37.4 प्रतिशत कंपनियों ने बताया कि वे अस्थायी श्रमिकों की नियक्ति अगले छह महीनों में बढ़ाने जा रही है। 50 प्रतिशत कंपनियां अगले छह महीनों में प्रबंधकीय और कुशल श्रमिकों के वेतन में भी बढ़ोतरी करने जा रही है। एनसीएईआर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले छह महीनों में कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होने की उम्मीद, मौजूदा निवेश का माहौल और वर्तमान में उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता के अधिकतम उपयोग से कारोबारी भरोसा सूचकांक में बढ़ोतरी हो रही है।

इस साल अप्रैल-जून तिमाही में 71.2 प्रतिशत कंपनियों ने माना कि देश की कुल आर्थिक स्थिति अगले छह महीनों में और बेहतर होगी जबकि इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में 65.8 प्रतिशत कंपनियों ने इस प्रकार का विश्वास जाहिर किया था। वहीं, अप्रैल-जून तिमाही में 67.4 प्रतिशत कंपनियों ने अपनी आर्थिक स्थिति अगले छह महीनों में और मजबूत होने का भरोसा जाहिर किया जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में 60.7 प्रतिशत कंपनियों ने इस प्रकार का भरोसा जाहिर किया था। अप्रैल-जून तिमाही में 97.8 प्रतिशत कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल कर रही थी।

गुड्स एक्सपोर्ट में भारत ने दर्ज की दोहरे अंक की वृद्धि, टॉप मार्केट बना हुआ है अमेरिका

इस वित वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही में आकर्षक पश्चिमी बाजारों में भारत के निर्यात में दोहरे अंकों की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है जो इकोनॉमी की प्रतिस्पर्धी ताकत को दर्शाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए आंकड़ों से पता चला है कि तिमाही के दौरान अमेरिका को भारत के निर्यात में 10 .4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि नीदरलैंड के मामले में 41.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 24) की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में प्रमुख पश्चिमी बाजारों में भारत के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो देश की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) को निर्यात में 10.4% की वृद्धि हुई, जबकि नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम को शिपमेंट में क्रमशः 41.3% और 21.9% की वृद्धि हुई। समृद्ध बाजारों जैसे सिंगापुर में 26.55% और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 17.6% निर्यात वृद्धि देखी गई।

अमेरिका है सबसे आगे

यानी कि इसमें अमेरिका टॉप बाजार बना हुआ है, जबकि चीन के साथ व्यापार घाटा कम हुआ। अमेरिका ने भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी, उसके बाद यूएई और नीदरलैंड का स्थान रहा। जबकि चीन को निर्यात में 2.8% की गिरावट आई, पड़ोसी देश से आयात में 8.3% की वृद्धि हुई, जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया।

विशेष रूप से, लाल सागर में हौथी हमलों और चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक व्यवधानों के बावजूद भारत ने लगातार तीन महीनों तक सकारात्मक निर्यात वृद्धि हासिल की।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बारे में आशा व्यक्त की, जिसमें उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत गतिविधि के साथ-साथ वैश्विक व्यापार में सकारात्मक गति का हवाला दिया गया। यह भारत की निर्यात संभावनाओं के लिए अच्छा संकेत है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बारे में आशा व्यक्त की, जिसमें उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत गतिविधि के साथ-साथ वैश्विक व्यापार में सकारात्मक गति का हवाला दिया गया। यह भारत की निर्यात संभावनाओं के लिए अच्छा संकेत है।

800 बिलियन डॉलर के निर्यात की राह पर भारत

गुड्स और सर्विसेज का निर्यात भारत के लिए जून में 65.47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 5.4% की वृद्धि को दर्शाता है।

इसके अलावा अप्रैल-जून तिमाही के लिए संचयी निर्यात में 8.4% की बढ़ोतरी हुई, जिसका कुल मूल्य 200.33 बिलियन डॉलर रहा।

मासिक आंकड़े जारी करते हुए व्यापार सचिव सुनील बर्थवाल ने उम्मीद जताई कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो वित्त वर्ष 24 के लिए भारत का कुल निर्यात 800 बिलियन डॉलर को पार कर सकता है।

पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम का रिप्लेसमेंट आया, क्या ये म्यूचुअल फंड से बेहतर होगा?

धीरेंद्र कुमार

कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट शुरू करने वाला है। वह इस प्रोडक्ट को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम (पीएमएस) और म्यूचुअल फंड के बीच एक बीच के प्रोडक्ट के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। सेबी ने कहा है कि यह पोर्टफोलियो बनाने में लचीलेपन के मामले में म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच एक नई एसेट क्लास का मौका है।

नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हाल में एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट शुरू करने की बात कही है। सेबी इस प्रोडक्ट को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम (पीएमएस) और म्यूचुअल फंड के बीच एक बीच के प्रोडक्ट के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। सेबी ने कहा है कि यह पोर्टफोलियो बनाने में लचीलेपन के मामले में म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच एक नई एसेट क्लास का मौका है। सेबी ने इस संबंध में लोगों से नाम सुझाने के लिए भी कहा है।

मेरा सुझाव है कि इसे पीएमएस कहा जाना चाहिए और जो प्रोडक्ट अभी पीएमएस होने का दावा करता है, उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। ये एक मजाक लगेगा, लेकिन मैं इसे लेकर थोड़ा गंभीर हूं। अगर आप इसकी तुलना मौजूदा म्यूचुअल फंड से करते हैं, तो मूल रूप से ये एक जैसे लगेंगे। हालांकि, अगर आप इसकी तुलना पीएमएस से करेंगे, तो ये एक बड़ा सुधार लगेगा। ये नया प्रोडक्ट, पीएमएस के दो बड़े नकारात्मक पहलुओं को खत्म कर देता है। पहला, टैक्स के लिहाज से उसकी अक्षमता और दूसरा, पारदर्शिता की कमी।

टैक्स की बात करें तो पीएमएस में, इन्वेस्टर की बुक में शेयर ट्रेड किए जाते हैं। हरेक ट्रेड, इन्वेस्टर के लिए एक अलग कैपिटल गेन या नुकसान के तौर पर माना जाता है, इसलिए कैलकुलेशन मुश्किल होती है और टैक्स ज्यादा लगता है। समय के साथ, टैक्स से निवेशकों का मुनाफा काफी कम हो जाता है। ये नया प्रोडक्ट, टैक्स के मामले में म्यूचुअल फंड जैसी सहूलियत देता है, जिसमें मुनाफे और नुकसान को फंड के भीतर ही एडजस्ट किया जाता है और केवल तभी टैक्स अदा करना होता है जब निवेशक अपनी यूनिट्स को भुनाता है।

पारदर्शिता की बात करें तो सेबी के प्रस्ताव के अनुसार, इस नए प्रोडक्ट के लिए हर महीने पोर्टफोलियो के डिस्क्लोजर और मूलभूत दस्तावेजों को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने की जरूरत होगी, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह। इतना ही नहीं, चूंकि ये एक पूल्ड यानी बहुत से निवेशकों का मिलाजुला फंड है, इसलिए स्टैंडर्ड एनएवी भी उपलब्ध होंगे, जिससे रिटर्न कैलकुलेट हो सकेगा और आपस में तुलना के साथ-साथ बेंचमार्किंग भी कैलकुलेट की जा सकेगी। पीएमएस के साथ ये सब संभव नहीं है। पारदर्शिता का ये स्तर पारंपरिक पीएमएस की तुलना में काफी बेहतर होगा।

इसके अलावा, जहां 10 लाख रुपये का प्रस्तावित न्यूनतम निवेश, ज्यादात म्यूचुअल फंड्स से ज्यादा है, वहीं पीएमएस के लिए जरूरी 50 लाख रुपये से काफी कम है। ये संभावित रूप से नई निवेश रणनीतियों और बहुत से नए निवेशकों के लिए रिस्क-रिटर्न के पैमाने पर दरवाजे खोल सकता है। बेशक, उम्मीद तो इसी बात की है। नई प्रस्तावित एसेट क्लास, पोर्टफोलियो बनाने को लेकर कई तरह की छूट देती है। इनमें डेट सिक्योरिटीज के लिए एक ही जारीकर्ता की बढ़ी हुई सीमा (एसेट का 20%, 10% से ज्यादा) होगी।

अलग-अलग क्रेडिट रेटिंग के लिए क्रेडिट रिस्क-आधारित एक ही जारीकर्ता की सीमा ज्यादा होगी और वोटिंग अधिकार के साथ प्रदत्त-पूंजी यानी पेड-अप कैपिटल के स्वामित्व की बढ़ी हुई सीमा (15%, 10% से ज्यादा) भी शामिल है। ये नई क्लास, किसी भी कंपनी की इक्विटी में ज्यादा निवेश की इजाजत देती है (15%, 10% से ज्यादा) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में निवेश की सीमा को दोगुना कर देती है।

अलग-अलग क्रेडिट रेटिंग के लिए क्रेडिट रिस्क-आधारित एक ही जारीकर्ता की सीमा ज्यादा होगी और वोटिंग अधिकार के साथ प्रदत्त-पूंजी यानी पेड-अप कैपिटल के स्वामित्व की बढ़ी हुई सीमा (15%, 10% से ज्यादा) भी शामिल है। ये नई क्लास, किसी भी कंपनी की इक्विटी में ज्यादा निवेश की इजाजत देती है (15%, 10% से ज्यादा) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में निवेश की सीमा को दोगुना कर देती है।

इसमें डेट सिक्योरिटीज के लिए सेक्टर स्तर की सीमा 20% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि जहां म्यूचुअल फंड्स को केवल हेजिंग और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल करने की अनुमति है। इस नए प्रोडक्ट को मार्केट रिस्क लेने के लिए भी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करने की इजाजत है। इन सभी राहतों का मकसद पोर्टफोलियो बनाने में ज्यादा लचीलापन लाना और बढ़े हुए रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करना है।

(लेखक धनक डाट काम के संपादक हैं और ये उनके निजी विचार हैं)

एयरपोर्ट पर सुधरे हालात, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर करने लगा काम; रद्द और विलंबित फ्लाइट्स में आई कमी

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को हालात सुधरे नजर आए। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी खराबी के कारण शुक्रवार को काफी फ्लाइट्स रद्द हुई थीं और विलंब भी हुईं। वहीं शनिवार को यह तकनीक में सुधार हुआ। इससे रद्द होने वाली उड़ानों की संख्या में कमी आई। इससे हवाई यात्रियों को राहत की सांस मिली है।

नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी खराबी के दुरुस्त होने से देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर शनिवार को हालात शुक्रवार के मुकाबले बदले-बदले नजर आए। कुछेक अपवादों को छोड़ दें तो अब एयरपोर्ट में प्रवेश से लेकर अंदर चेकइन की प्रक्रिया सामान्य होने लगी है। सुबह कुछ दिक्कत सामने आई लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन बीतता गया, हालात सामान्य होते गए। एयरपोर्ट पर हालात सामान्य होने से यात्रियों में काफी राहत है।

रद्द उड़ानों की संख्या घटकर पहुंची 11

शुक्रवार को जहां रद्द उड़ानों की संख्या 47 थी। वहीं, शनिवार को यह संख्या घटकर 11 पहुंच गई। जिन भी उड़ानों को रद्द किया गया है, उनके ऑपरेटर का साफ-साफ कहना है कि यह ऑपरेशनल कारणों से हो रहा है। इसका सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी से कोई लेनादेना नहीं है।

एयर इंडिया ने क्या कहा

एयर इंडिया ने तो शुक्रवार को अपनी रद्द उड़ानों के बारे में शनिवार को स्थिति स्पष्ट की और कहा कि सॉफ्टवेयर गड़बड़ी से शुक्रवार को कोई उड़ान रद्द नहीं हुई। शनिवार को जो उड़ानें रद्द हुईं, उनमें एअर इंडिया एक्सप्रेस की गोआ, इंडिगो की अहमदाबाद, पटना, एअर इंडिया की इदौर, रांची, भोपाल, मुंबई व अकासा की गोरखपुर की उड़ानें शामिल थी।

विलंबित उड़ानों की संख्या भी हुई कम

शनिवार को शुक्रवार के मुकाबले विलंबित उड़ानों की संख्या में भी काफी कमी देखी गई। करीब 75 उड़ानें विलंबित रहीं। इनमें से एक दर्जन उड़ानों को छोड़ दें तो शेष सभी उड़ानें एक घंटा या इससे भी कम की देरी से गंतव्य के लिए रवाना हुई।

विलंबित उड़ानों में सर्वाधिक संख्या इंडिगो की उड़ानों की रही। इसके बाद स्पाइसजेट व एयर इंडिया का स्थान रहा। सर्वाधिक विलंब से एलायंस एयर की अहमदाबाद की उड़ान करीब साढ़े चार घंटे की देरी से रवाना हुई।

डिजियात्रा करने लगा काम

शनिवार को डिजियात्रा के उपयोगकर्ता यात्रियों में इस बात को लेकर संशय की स्थिति थी कि यह सिस्टम एयरपोर्ट पर काम कर रहा है या नहीं। कई यात्रियों ने इस बारे में एक्स पर दिल्ली एयरपोर्ट को टैग करते हुए सवाल पूछा।

दिल्ली एयरपोर्ट संचालन एजेंसी डायल ने कहा कि डिजियात्रा पूरी तरह काम कर रहा है। हालांकि यात्रियों का कहना है कि सुबह में कुछ समय के लिए सिस्टम में कुछ दिक्कत आई लेकिन इसे दुरुस्त कर लिया गया। इसी तरह सुबह अलग-अलग जगहों पर टर्मिनल के भीतर लगे स्क्रीन बोर्ड पर भी कुछ समस्या आई, लेकिन यह भी ठीक हो गया।

तीन पुलिस थानों में CBI के छापे, पांच पुलिसकर्मी रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस में इन दिनों भ्रष्टाचार चरम पर है। यही कारण है कि सीबीआई ने तीन थानों में छापेमारी कर पांच पुलिसकर्मियों को रिश्वत के आरोप में धर दबोचा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब CBI को तीन थाना पुलिस के बारे में रिश्वत लेने की शिकायत मिलनी थी। इतना ही नहीं कुछ के घर और सरकारी परिसरों में भी तलाशी ली गई।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली के तीन थानों में छापेमारी कर पांच पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते ही एजेंसी ने ज्योति नगर थाने के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को 50 हजार रिश्वत लेते कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया था।

दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार चरम पर

ऐसा पहली बार हुआ है, जब तीन थाना पुलिस (Delhi Police) के बारे में रिश्वत लेने की शिकायत मिलने पर सीबीआई ने पांच पुलिसकर्मियों को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार चरम पर है। आलम यह है की हर माह दो-तीन थानों में सीबीआई छापेमारी कर पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर रही है।

पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। एजेंसी द्वारा छापेमारी किए गए पुलिस थानों में से एक पूर्वी दिल्ली का पटपड़गंज थाना है, जिसकी डीसीपी अपूर्वा गुप्ता हैं। सूत्रों ने बताया कि यहां से हवलदार सुधाकर और राजकुमार को पकड़ा गया है। एक अन्य छापेमारी हौज खास थाने में की गई, जहां से एक एसआई को गिरफ्तार किया गया।

सीबीआई आज दे सकती है मामले में ब्रीफिंग

गोविंदपुरी थाने में तैनात एक हवलदार को भी रिश्वत की रकम के साथ पकड़ा है। सीबीआई शनिवार को मामले पर ब्रीफिंग दे सकती है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने कुछ शिकायतें मिलने के बाद मामले दर्ज किए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ पुलिसकर्मी अलग-अलग मामलों में कुछ शिकायतकर्ताओं से रिश्वत मांग रहे थे।

सीबीआई ने इसके बाद शुक्रवार शाम छापेमारी कर पांच पुलिसकर्मियों को दबोच लिया। एक अधिकारी ने कहा कि पुलिसकर्मी के आवासीय और सरकारी परिसरों पर भी तलाशी ली गई। यह पिछले पखवाड़े में दिल्ली पुलिस के कर्मियों पर सीबीआई की कार्रवाई का चौथा उदाहरण है। बल के इतिहास में अभूतपूर्व कार्रवाई में इस साल भ्रष्टाचार के आरोप में कम से कम दो दर्जन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा हटाया गया रास्ते से अतिक्रमण

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा। उपखण्ड अधिकारी निरमा विश्नोई की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम तहसीलदार शाहपुरा, भू०अ०निरीक्षक बोरड़ा एवं पटवार हल्का बोरडा के साथ पटवार मण्डल बोरड़ा के ग्राम फतेहपुरा की बिलानाम भूमि में वर्षों से चालू रास्ते पर हो रखे अतिक्रमण को हटवाया गया। प्रार्थी रतन भील निवासी फतेहपुरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में रास्ते हेतु प्रकरण दर्ज करवाया गया। जिसमें ज्ञात हुआ कि ग्राम फतेहपुरा की बिलानाम भूमि में से प्रार्थी के खेतों पर जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण पाया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटवाये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया गया। आदेश की पालना में राजस्व विभाग की टीम तहसीलदार शाहपुरा, भू०अ०निरीक्षक बोरड़ा एवं पटवार हल्का बोरड़ा के साथ स्वयं उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंच रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया।

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर निर्णय सुरक्षित, 2 अगस्त को आ सकता है फैसला

31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। सत्र अदालत ने अगस्त 2023 में इस मामले में टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी थी। अदालत ने टाइटलर को निर्देश दिया था कि वह न तो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे और न ही बिना अदालत की अनुमति के देश छोड़कर जाएंगे।

नई दिल्ली। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में तीन लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के विरुद्ध आरोप तय करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने सीबीआई और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद कहा कि फैसला दो अगस्त को सुनाया जा सकता है। सीबीआई ने एक गवाह के हवाले से आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि टाइटलर एक नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों को मारने के लिए उकसाया था। यह भी आरोप लगाया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर ने भीड़ से कहा था कि सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है। टाइटलर के कारण तीन लोगों की हत्या हुई थी।

टाइटलर को अदालत ने 2023 में जमानत दी थी

31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। सत्र अदालत ने अगस्त 2023 में इस मामले में टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी थी। अदालत ने टाइटलर को निर्देश दिया था कि वह न तो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे और न ही बिना अदालत की अनुमति के देश छोड़कर जाएंगे। सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (अपराध को उकसाना) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं।

आधुनिकीकरण की कमी के लिए पुस्तकालयों में कम उपस्थिति भी जिम्मेदार है : विजय गर्ग

पुस्तकालयों में पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं जो हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान कर सकती हैं। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करने से न केवल हमारी समझ और सोच का विस्तार होता है बल्कि हमें आत्म-ज्ञान और मानसिक शांति भी मिलती है। किताबें हमें अपने विचारों को स्पष्ट और सकारात्मक दिशा देने में मदद करती हैं जिसके माध्यम से हम अपने आंतरिक संघर्षों और परेशानियों पर काबू पा सकते हैं। आज के समय में सतर्क रहना बहुत जरूरी है औरइन पुस्तकों को पढ़ने से अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करने में मदद मिल सकती है। किताबों में छिपी ज्ञान की रोशनी न सिर्फ हमें सही दिशा दिखाती है, बल्कि हमारी सोच को भी व्यापक और समृद्ध बनाती है। आजकल बच्चों की किताबों के प्रति रुचि धीरे-धीरे कम होती जा रही है। पुस्तकालयों की घटती संख्या और उनमें बच्चों की घटती उपस्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. डिजिटल युग का प्रभाव आज के बच्चों पर सबसे ज्यादा है। स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर का उदयबढ़ते उपयोग के कारण बच्चे डिजिटल सामग्री में अधिक रुचि ले रहे हैं। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में व्यस्त जीवनशैली भी एक कारण है। पुस्तकालयों में कम उपस्थिति के लिए पुस्तकालयों की गैर-आधुनिकता भी जिम्मेदार है। आज भी कई पुस्तकालय पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं। पुस्तकालय सेवाओं के बारे में प्रचार-प्रसार और जानकारी का अभाव भी बच्चों को आकर्षित करने में बाधक बनता है। इस समस्या के समाधान के कदमों में डिजिटल सामग्री को शामिल करना शामिल है। पुस्तकालयई-पुस्तकों और ऑडियो-पुस्तकों की व्यवस्था की जा सकती है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। पुस्तकालय आरामदायक बैठने की जगह, इंटरनेट सुविधा और अन्य आकर्षक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए माता-पिता और शिक्षकों को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इन प्रयासों से बच्चों में किताबों के प्रति रुचि बढ़ सकती है और पुस्तकालयों की उपयोगिता बहाल हो सकती है।

तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम

दुनिया के सभी विकसित देशों ने अपनी शिक्षा प्रणाली को नई तकनीक से मजबूत किया है और उन देशों ने वैज्ञानिक, अनुसंधान, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया है लेकिन हमारे देश की शिक्षा प्रणाली इन देशों की तुलना में बहुत पीछे है। तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम हर साल 15 जुलाई को पूरी दुनिया में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार, अच्छे काम, देश और अपनी प्रगति के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के महत्व पर जोर देना हैस्वीकार करना होगा आज देश और दुनिया में विकसित हो रही प्रौद्योगिकी और बदलते श्रम बाजार की गतिशीलता को देखते हुए युवाओं को आधुनिक और बहुमुखी कौशल से लैस करना आवश्यक हो गया है। हर विकसित देश की प्रगति के पीछे एक अच्छी शिक्षा प्रणाली का बड़ा योगदान रहा है। दुनिया के सभी विकसित देशों ने अपनी शिक्षा प्रणाली को नई तकनीक से मजबूत किया है और उन देशों ने वैज्ञानिक, अनुसंधान, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया है लेकिन हमारे देश की शिक्षा प्रणाली नहीं हैअन्य देशों की तुलना में यह काफी पीछे है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शिक्षा का व्यावसायीकरण जरूरी है। जिसके अनुसार पूरे विश्व में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन/अनुमोदित पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। यदि पंजाब में आई.टी.आई. वोकेशनल कोर्स की बात करें तो यहां कई वोकेशनल कोर्स भी संचालित होते हैं। (आईटीआई) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 1950 में शुरू हुआ और यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आईटीआई के तहत कई तकनीकी पाठ्यक्रम पेश किए जाते हैं। जिसमें लगभगपाठ्यक्रम छह महीने से लेकर दो या तीन साल तक की अवधि के होते हैं। आठवीं पास छात्रों के पास प्लंबर कोर्स, ट्रैक्टर, मैकेनिक, लकड़ी का काम (लकड़ी का खराद), खेल का सामान बनाना, चमड़े का सामान बनाना, सिलाई, सुई का काम, वेल्डर (बिजली और गैस), बढ़ई, फाउंड्रीमैन जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी कई विकल्प हैं एवं सीट मेकर वर्कर आदि का एक वर्षीय कोर्स किया जा सकता है। दो साल के वोकेशनल कोर्स की बात करें तो वायर मैन और पेंटर (जनरल) जैसे कोर्स किए जा सकते हैं।

सेवानिवृत्त प्राचार्य शिक्षा स्तंभकार मलोट

संबलपुर स्टेशन से संबलपुर सिटी स्टेशन तक 8.10 किलोमीटर लंबे रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 288.61 करोड़ रुपये मंजूर

मनोरंजन सासमल, स्टेटे हेड उडीशा

भुबनेस्वर : रेल मंत्रालय ने रेल यातायात में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संबलपुर स्टेशन से संबलपुर सिटी स्टेशन तक 8.10 किलोमीटर लंबे रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 288.61 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्देश्य ट्रेनों की क्षमता बढ़ाना और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। रेल फ्लाईओवर संबलपुर के सभी तरफ से एक साथ ट्रेन की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा और टिटिलागढ़, अंगुल और एक साथ बाधा मुक्त संचालन सुनिश्चित करेगा। झारसुगुड़ा पक्ष करेंगे

x परिचालन दक्षताः क्रॉस-ट्रैफ़िक देरी और परिचालन अक्षमताओं को समाप्त करके, यह महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्र में ट्रेनों की औसत गति और दक्षता में वृद्धि करेगी।

x ऊर्जा गलियारा योजनाः इस परियोजना का निर्माण भारतीय रेलवे के ऊर्जा गलियारे का हिस्सा है जो टिकाऊ और कुशल बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।

x लंबाई और लागतः 8.10 किमी लंबाई के इस महत्वपूर्ण रेलवे फ्लाईओवर के लिए 288.61 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

भारतीय रेलवे देश भर में अपने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है सांवलपुर में यह नया प्रस्तावित रेलवे फ्लाईओवर ट्रेन यात्रा के समय को कम करेगा और ट्रेन आंदोलन की दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अंततः, यह रेल फ्लाईओवर यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने और क्षेत्र में भारतीय रेलवे की दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा।

गुरु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन हैं गुरुपूर्णिमा : डॉ उमेश शर्मा

परिवहन विशेष न्यूज

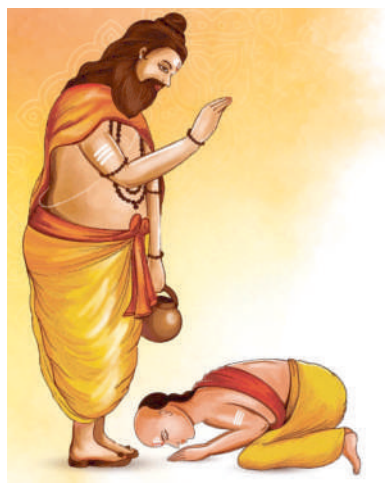

आगरा। गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतिबिंब होता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन ग़रीब जरुरतमंन्दों में दान-पुण्य का विशेष महत्व होता है।

इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी डॉ उमेश शर्मा ने सभी को गुरू पूर्णिमा पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि हर उस व्यक्ति को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं जिन्होंने किसी के जीवन में प्रकाश लाया और उन्हें सही रास्ता दिखाया। क्योंकि गुरू बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लवै न सत्य को, गुरु बिन मैटैं न दोष। उन्होंने कहा, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और उन्हें गुरु दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु और गुरु तुल्य वरिष्ठजनों को मान-सम्मान देते हुए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देने का भी महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान-पुण्य और पूजा-पाठ का भी बहुत महत्व है। माना जाता है कि जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और ग़रीब, जरुरतमन्दों में दान-पुण्य करता है, उसे जीवन में सुःख शांति एवं ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि गुरु पूर्णिमा का मुख्य उद्देश्य गुरुओं का सम्मान करना और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। गुरु हमें ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। गुरु पूर्णिमा ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। इस दिन हम अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं और जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का वचन देते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन हम अपने गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त करके सत्य और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।

जिला कलक्टर ने सालरिया ग्रामवासियों की सुनी परिवेदनाएं

बनेडा तहसील की ग्राम पंचायत सालरिया में जिला कलक्टर की रात्रि चौपाल आयोजित

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा जिला कलक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने ज़िले की बनेडा तहसील के सालरिया

ग्राम में रात्रि चौपाल में ग्राम वासियों की परिवेदनाओं को सुना और अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेते हुए निस्तारण के निर्देश दिए। शुक्रवार को आयोजित रात्रि चौपाल में ग्राम वासियों ने सालरिया

संबंधित परिवेदनाओं को प्रमुखता से रखा।

अधिकारियों से मौके पर ही दिलवाई जानकारी

जिला कलक्टर शेखावत ने प्रत्येक आई हुई परिवेदना पर मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारी से ग्रामवासियों को तथ्यात्मक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाई।

रात्रि चौपाल में लगभग 34 परिवेदनाएँ प्राप्त हुई जिसमे से क़रीब 10 परिवेदनाओं का मौक़े पर ही ज़िला कलेक्टर द्वारा निस्तारण किया गया। रात्रि चौपाल में बिजली, पानी तथा खाद्य सुरक्षा के संबंध में प्राप्त परिएदनाओ के बारे में भी अधिकारियों ने ग्राम वासियों को जानकारी प्रदान की।

रात्रि चौपाल में आई परिवेदनाओं पर जिला कलक्टर शेखावत ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

इस दौरान एसडीएम व्यास, बीडीओ धर्मपाल, तहसीलदार चोखाराम,

सांसारिक आसक्तियों से हटकर भक्ति वैराग्य से परमात्मा की ओर अग्रसर हो -आचार्य शक्ति देव महाराज

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। श्री पुराना शहर माहेश्वरी सभा भीलवाड़ा के तत्वाधान मे सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव के तहत

तृतीय दिवस की कथा में आचार्य शक्ति देव महाराज ने सृष्टि की उत्पत्ति कपिल देवहुती संवाद, ध्रुव चरित्र, सती चरित्र इत्यादि कथाएं श्रवण कराई, कथा में मनोहर झांकियां के माध्यम से शिव पार्वती के विवाह का आनंद लिया, 21 जुलाई को राम कथा एवं कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा कथा स्थल को आकर्षक रूप से गुब्बारों एवं फूलों से सजाया जाएगा

मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि तृतीय दिवस की कथा में महाराज ने कहा कि मन जब सांसारिक विषय आसक्तियों में लीन रहता है तब जीव अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा रहता है जिसके कारण जीव को देह गेह के प्रति मैं और मेरेपन का दुराग्रह होता है जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन को ही माना गया है मोक्ष का मतलब होता है मोह माया ममता को अपने हृदय से नष्ट कर देना ही मोक्ष कहलाता है मन विषयों में आसक्त होने पर बंधन का हेतु होता है परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बनता है इसलिए जीव को इस मन को सांसारिक विषय आशक्तियों से हटाकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त कर परमात्मा के प्रति अग्रसर करना चाहिए तभी आत्म कल्याण होगा जिस जीव ने अपने मन को साध लिया उसका जीवन संवर जाएगा मन को साधने के कुछ साधन बताए हैं जिसमें चार प्रमुख साधन हैं अपने आसन को जीते प्राणायाम करें अपनी संगति को जीते और अपनी इंद्रियों को जीते सबसे सरल साधन है संगति से आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों की संगति करना प्रारंभ कर दीजिए जीवन संवर जाएगा

कथा से पूर्व भागवत जी की आरती में अनिल बांगड़, जगदीश कोगटा, अशोक काबरा, प्रहलाद अजमेरा, सुरेश कचोलिया, सत्यनारायण न्याती, शांतिलाल पोरवाल, गजानन बजाज, रमेश राठी, रामगोपाल झवर, कैलाश काबरा, मुकेश सोमानी, शिवकुमार लाहोटी, जगदीश जागा सहित सैकड़ों जन उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023